सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 251 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 24 जून 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

सड़क पर बेकाबू सांड का तांडव, सींग से उठाकर बुजुर्ग को पटका

कोरबा। बुधवार सुबह शहर की पुरानी बस्ती के कराते चौक पर सांड के हमले से हड़कंप मच गया। एक आवारा सांड ने राह चलते आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया। हमले की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 55 वर्षीय छोटे लाल श्रीवास अपने काम से जा रहे थे, तभी सांड ने उनपर अचानक हमला किया। सांड ने बुजुर्ग को सींगों पर उठाकर जमीन पर पटक दिया। गंभीर चोटों के कारण छोटे लाल श्रीवास की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी जिंदगी और मौत से जूझने की स्थिति बनी हुई है। वार्ड पार्षद तामेश अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से इस खूंखार सांड को तुरंत पकड़ने की मांग की है।

शराब की दुकान के पास मिली युवक की लाश

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र स्थित शराब की दुकान में एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान खेरथा गांव निवासी पवन निषाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शराब भट्टी के अंदर टेबल पर पवन निषाद का शव पड़ा मिला, जबकि दूसरी ओर एक युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही जामुल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है।

मुंबई लोकल ट्रेन में यात्री की चाकू मारकर हत्या

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में दरवाजा बंद करने को लेकर हुए विवाद ने एक यात्री की जान ले ली। पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम मयंक लोहार है। वह अंधेरी वेस्ट स्थित वेस्टसाइड स्टोर में ड्यूटी करके घर लौट रहा था। मयंक चर्चगेट-नालासोपारा लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में था। तेज बारिश के बीच कोच का दरवाजा बंद रखने को लेकर उनकी एक अन्य यात्री से विवाद हुआ। इसी बहस में आरोपी ने मयंक के पेट में चाकू घोंपा था। इसये उसकी मौत हो गई।

अवैध गुटखा फैक्ट्री पर रेड : वॉशिंग पावडर की आड़ में बन रहा था गुटखा

दुर्ग पुलिस की टीम ने मंगलवार रात को दी दबिश, भारी मात्रा में गुटखा का कच्चा माल बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। अवैध रूप से गुटखा निर्माण पर दुर्ग जिले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मंगलवार की रात को दुर्ग पुलिस की टीम ने कचांदूर स्थित एक गोदाम में रेड कार्रवाई कर भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान व कच्चा माल जब्त किया है। खास बात यह है कि गोदाम को वॉशिंग पाऊडर पैकिंग के नाम पर किराए पर लिया गया था और अवैध रूप से जर्दा युक्त गुटखा तैयार और पैकेजिंग का काम किया जा रहा था। मामला जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार कचांदूर का उक्त गोदाम सुपेला में रहने वाले मोहम्मद मुस्तफा का है। गोदाम को उत्तर प्रदेश उन्नाव के रहने वाले मोहम्मद सानू ने करीब 20 दिन पहले किराए पर लिया था गोदाम लेने के दौरान उसने डिटर्जेंट

पाउडर निर्माण व उसकी पैकेजिंग की जानकारी दी थी। इसके बाद मो सानू का गोदाम मालिक से संपर्क नहीं हुआ। बाद में किराएदार का मोबाइल बंद आने लगा। गोदाम मालिक ने उससे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसी दौरान गोदाम के आसपास संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने लगी। वहीं, परिसर में तैनात गार्ड ने भी मालिक को अंदर कुछ गड़बड़ी होने की आशंका जताई। शक बढ़ने पर मोहम्मद मुस्तफा ने जेवरा सिरसा चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी की तलाश में पुलिस

जेवरा पुलिस ने बताया कि गोदाम मालिक मो मुस्तफा की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान गुटखा निर्माण से जुड़ा कच्चा माल और पैकिंग सामग्री बरामद हुई है। आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस की दबिश में गुटखा व कच्चा माल बरामद

सूचना के बाद जेवरा सिरासा पुलिस ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी और छापामार कार्रवाई की प्लानिंग की गई। मंगलवार रात को जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने गोदाम में दबिश दी। गोदाम की जांच की तो जांच के दौरान वहां से 32 बड़े बोरों में तैयार गुटखा,32 बोरों में मीठी सुपारी, गुटखा बनाने में उपयोग होने वाला रॉ मटेरियल और मिक्सिंग मशीन बरामद किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फूड सेफ्टी विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गोदाम में अवैध गुटखा की पैकेजिंग और निर्माण का कार्य किया जा रहा था। बरामद सामग्री को फुड सेफ्टी अधिकारियों को सौंपा गया है।

खिड़की उखाड़कर बाल सुधार गृह से भाग गए 11 अपचारी बालक

■ हत्या-रेप और लूट मामलों में थे बंद

श्रीकंचनपथ न्यूज

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल संप्रेक्षण गृह से 11 नाबालिग लड़के खिड़की उखाड़कर भाग गए। ये सभी हत्या, रेप, लूट और अन्य गंभीर मामलों में अंदर थे। खराब मौसम, तेज बारिश और बिजली गुल होने का फायदा उठाकर नाबालिगों ने एक बैरक की खिड़की पूरी तरह उखाड़ दी और वहां से बाहर निकल गए। इसके बाद वे संप्रेक्षण गृह की दीवार फांदकर फरार हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे तेज बारिश के कारण बिजली गुल हो गई। इसी दौरान 11 नाबालिगों ने बैरक की खिड़की उखाड़ दी और वहां से फरार हो गए। बाल संप्रेक्षण गृह के हाउस फादर मनीष कुशवाहा ने बताया कि शाम को खाने के बाद सभी बच्चे अपने-अपने कमरे में चले गए थे। कुछ बच्चे टीवी देख रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश और गरज-चमक के बीच बिजली चली गई। मौके का फायदा उठाकर कुछ नाबालिगों ने खिड़की उखाड़ दी और 11 फरार हो गए। इन अपचारी बालकों को चोरी, लूट, दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के अलग-अलग मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था।

नाबालिगों के एक साथ फरार होने की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने शहर के प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और संभावित ठिकानों पर लगातार जांच की जा रही है। पुलिस ने फरार लड़कों के गृह जिलों की पुलिस को भी सूचना दे दी है। उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी फरार लड़कों को पकड़ लिया जाएगा।

देर से आए मानसून के बाद भी आधे से ज्यादा हिस्सा कवर, एक सप्ताह तक का अलर्ट

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से सक्रिय हो गया है। 22 जून को दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करने के बाद मानसून ने महज 24 घंटे के भीतर राज्य के लगभग 75 प्रतिशत हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कबीरधाम जिले के शेष इलाकों में भी मानसून दस्तक दे सकता है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना जताई गई है।

राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में मंगलवार शाम हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई। बारिश के असर से प्रदेशभर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मंगलवार को प्रदेश का सर्वाधिक तापमान बिलासपुर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान राजनांदगांव में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली को

लेकर चेतावनी जारी की है। ऑरेंज अलर्ट के तहत कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं यलो अलर्ट के तहत सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर सहित कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।

नारायणपुर में 26 ईसाई परिवारों को गांव से बाहर निकाला, पेड़ के नीचे रहने मजबूर

श्रीकंचनपथ न्यूज

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। ईसाई धर्म को मानने वाले 26 परिवारों का आरोप है कि मंगलवार को गांव के कुछ ग्रामीणों ने उन्हें गांव छोड़ने का फरमान सुनाया और घरों से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभी परिवार गांव के बाहर पेड़ों की छांव में रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि वे गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि यदि ये सभी परिवार मूल धर्म में लौट आए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने गांव में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी है। फ्लिहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मामला भरेंडा थाना क्षेत्र के भरेंडा गांव का है। बताया जा रहा है कि, दिसंबर 2025 से गांव का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। बीच-बीच में विवाद की घटनाएं सामने आती रहीं, लेकिन 9 जून 2026 के बाद से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। उस दिन दोनों

पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना में कुछ महिलाओं के घायल होने की भी सूचना मिली थी।

क्रिकेटर रोहित शर्मा सहित 65 हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में पद्म अवॉर्ड के दूसरे फेज में 65 हस्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री दिए गए। इस दौरान राष्ट्रपति ने क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक्टर आर माधवन को पद्मश्री से नवाजा गया। पुरस्कार पाने वालों में एक्टर ममूटी और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज भी शामिल रहे।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस को जनसेवा, सीनियर मलयालम जर्नलिस्ट पी नारायणन को साहित्य के लिए पद्म विभूषण दिया गया। झारखंड के पहले

मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। अवॉर्ड लेने उनकी पत्नी रूपी सोरेन पहुंची। सिंगर अलका याग्निक ने अवॉर्ड लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए।

कुत्तों ने चीतल पर किया हमला

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जीपीएम के अमरपुर स्थित पुलिस लाइन परिसर में आज एक नर चीतल पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। जंगल से भटककर आबादी क्षेत्र में पहुंचे चीतल को कुत्तों ने घेर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस लाइन के जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से चीतल की जान बच सकी। जानकारी के अनुसार, नर चीतल भोजन या पानी की तलाश में जंगल से भटककर पुलिस लाइन परिसर में आ गया था। इसी दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस जवानों ने कुत्तों को खदेड़कर चीतल को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी और वन्यजीव बचाव दल मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने चीतल को वन्यजीव बचाव वाहन से पशु चिकित्सालय पेंड्रा पहुंचाया। पशु चिकित्सकों ने उसका उपचार किया।

सजगता और तत्परता से टली बड़ी रेल दुर्घटना, वरिष्ट पत्रकार टी सूर्याराव का रेल प्रशासन ने किया सम्मान

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। 22 मई को पावर हाउस रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट के बोल्ट निकले हुए दिखाई दिए। यह स्थिति अत्यंत गंभीर थी और समय रहते सुधार नहीं होने पर किसी बड़ी रेल दुर्घटना का कारण बन सकती थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए वरिष्ट पत्रकार टी. सूर्याराव द्वारा इसकी सूचना तत्काल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रायपुर रेल मंडल (सीनियर डीसीएम) अवधेश कुमार त्रिवेदी को दी गई।

सूचना प्राप्त होते ही श्री त्रिवेदी

ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर-2 से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश दिए। रेलवे के तकनीकी दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ट्रैक की मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्य पूरा किया। सुरक्षा मानकों की पुष्टि होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन पुन: शुरू किया गया।

सीनियर डीसीएम ने बताया कि यदि समय पर सूचना नहीं मिलती तो एक बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जानकारी से रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद को भी अवगत कराया। रेल सुरक्षा के प्रति दिखाई गई इस सजगता के लिए रेल प्रशासन रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा टी सूर्याराव को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रेलवे वाणिज्यिक विभाग के निरीक्षक बाबूराव टाटा, कलिंगा समाज रायपुर के अध्यक्ष जगदीश्वर राव तथा विष्णु केमिकल भिलाई के वाइस प्रेसिडेंट एमवी राव विशेष रूप से उपस्थित रहे।

संपादकीय

सुखपुरी के सुख-दुख

फोन तोड़ना बड़े संकट का छोटा समाधान

आज स्मार्टफोन के बच्चों व किशोरों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों से पूरी वैश्विक बिरादरी फिक्रमंद है। लाइलाज मर्ज बनती इस लत के खिलाफ परंपरागत समाजों व विकासशील देश ही नहीं, बल्कि आस्ट्रेलिया, फ्रांस,ब्रिटेन आदि विकसित देशों में भी एक उम्र के बाद ही स्मार्ट फोन के इस्तेमाल करने के लिए कानून बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जनक अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ अदालतों में मोटे मुआवजे वसूले गए हैं। इसी बीच हरियाणा के नूंह जिले के सुखपुरी गांव में एक अभिनव पहल हुई है। यूं तो स्मार्टफोन आज आवश्यक बुराई बनते जा रहे हैं, लेकिन सुखपुरी के दुख अलग हैं। गांव की पहचान साइबर क्राइम के हब के रूप में होने लगी है। आये दिन गांव में पुलिस की दस्तक से उन्हें बदनामी महसूस होती है। उनका कहना है कि इस गांव के कुछ युवाओं के साइबर क्राइम में शामिल होने के आरोपों के चलते बाहरी ग्रामीण गांव में रिश्ते करने से कतरा रहे हैं। गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने 55 मोबाइल हैंडसेट पटककर तोड़ दिए। उनका मकसद गांव को साइबर क्राइम हब के दाग से मुक्त कराना था। ग्रामीणों ने जरूरत के लिये बेसिक फोन इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। बताते हैं कि नूंह क्षेत्र के 57 गांवों के लोगों ने भी ऐसी पहल करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी में बड़े-बुजुर्गों के फैसले के खिलाफ गुस्सा है। उनका मानना है कि इस फैसले से उनकी आर्थिक प्रगति बाधित होगी। कई लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निर्भर है। उनकी दलील है कि महज कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी पीढ़ी को नहीं दी जा सकती। वे ऑनलाइन पढ़ाई व स्कॉलरशिप पोर्टल से कट जाएंगे। वहीं यूपीआई पेमेंट समेत ऑनलाइन भुगतान के तौर-तरीके बाधित होंगे। लेकिन सुखपुरी के लोगों के गांव का नाम साइबर क्राइम से जुड़ने के दुख को भी समझने की जरूरत है।

> गांव की पहचान साइबर क्राइम के हब के रूप में होने लगी है। आये दिन गांव में पुलिस की दस्तक से उन्हें बदनामी महसूस होती है। उनका कहना है कि इस गांव के कुछ युवाओं के साइबर क्राइम में शामिल होने के आरोपों के चलते बाहरी ग्रामीण गांव में रिश्ते करने से कतरा रहे हैं। गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने 55 मोबाइल हैंडसेट पटककर तोड़ दिए। उनका मकसद गांव को साइबर क्राइम हब के दाग से मुक्त कराना था। ग्रामीणों ने जरूरत के लिये बेसिक फोन इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। बताते हैं कि नूंह क्षेत्र के 57 गांवों के लोगों ने भी ऐसी पहल करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी में बड़े-बुजुर्गों के फैसले के खिलाफ गुस्सा है।

सही मायने में आज जरूरत एक बीच का रास्ता तलाशने की है। ताकि साइबर क्राइम में युवाओं के लिप्त होने से गांव की बदनामी भी न हो, और डिजिटल गतिविधियां भी चलती रहें। निस्संदेह, तकनीक को धोखा देने और गैर-कानूनी फायदा उठाने का जरिया नहीं बनने दिया जाना चाहिए। नियामक एजेंसियों को सामुदायिक नेताओं की मदद से ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए, जो अक्सर साइबर फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन स्कैम में लिप्त रहते हैं। वाकई आज स्मॉर्ट फोन दुधारी तलवार बन गए हैं। ऐसा जिन्न, जिसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। जिसकी वजह से तुरंत पैसा कमाने के फेर में युवा साइबर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। सवाल केवल साइबर अपराधों का ही नहीं है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों में अश्लील सामग्री का बोलबाला है। जिससे किशोर व युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। कई तरह की भाषाई विकृतियां सामने आ रही हैं। समय व पैसा बचाने के लिये शादियों के कार्ड व्हाट्स ऐप के जरिये भेजने का प्रचलन तो बढ़ा है, लेकिन इससे विवाह समारोह के आमंत्रण की गरिमा व प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। ये स्पष्ट है कि आज स्मॉर्ट फोन सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये शिक्षा, बैंकिंग,सरकारी सेवाओं, रोजगार के मौके तलाशने व वीडियो कॉलिंग का जरिया भी हैं। ऐसे समय में, जब गांवों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये डिजिटल कनेक्टिविटी अपरिहार्य है, स्मार्टफोनों के उपयोग से युवाओं को पूरी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता। डिजिटल दौर में उन युवाओं के भी अलग-थलग पड़ने की आशंकाएं हैं, जिनका भविष्य बचाने के लिये यह पहल की जा रही है। दरअसल, मुद्दा स्मॉर्ट फोन डिवाइस का नहीं है, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल का है। जिसे समाज में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल की कमी और रातों-रात अमीर बनने की चाह बढ़ावा देती है। ऐसे कृत्यों के कानूनी नतीजों से युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। इस संकट के मूल को तलाशकर, उसका उपचार करना जरूरी है। आवश्यकता डिजिटल दुनिया से कटने की नहीं, बल्कि साइबर साक्षरता व डिजिटल जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की है। बहरहाल, सुखपुरी की सामूहिक कार्रवाई और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए।

नया भारत संदेह से भरोसे की ओर और डर से आजादी की ओर बढ़ रहा है

पीयूष गोयल

दशकों तक, भारत की नियामक प्रणाली नागरिकों को गहरे अविश्वास की नज़र से देखती थी। नागरिकों को मामूली, प्रक्रियात्मक गलतियों या किसी अधिकारी के केवल शक के आधार पर अपराधी मान लिया जाता था। एक सुखद बदलाव के तौर पर, मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए भरोसे और सहानुभूति पर आधारित नीतियां बनाई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों और व्यवसायों का समर्थन करने, अनुपालन को सरल बनाने और व्यवसायों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भारत के कानूनी परिदृश्य में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे अनुपालन बोझ कम करना हो, डिजिटलीकरण हो, या एकल-खिड़की मंजूरी हो, कुल मिलाकर बदलाव का मकसद शासन को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाना रहा है।

प्रधानमंत्री का विश्वास और सहानुभूति पर आधारित शासन का मंत्र स्पष्ट रूप से जन विश्वास अधिनियम, 2026 और 2023 के इसी तरह के एक कानून में दिखाई देता है।

नागरिक-अनुकूल - एक नागरिक-अनुकूल नियामक वातावरण बनाने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, नया कानून मामूली अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट सिद्धांत अपनाता है: दंड से पहले चेतावनी देना, अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना तय करना, त्वरित और पारदर्शी समाधान और जुर्माने का एक गतिशील ढांचा, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता हो, ताकि नियम लागू करने का तरीका प्रभावी, प्रासंगिक और समय के साथ उत्तरदायी बना रहे।

यह नियामक दृष्टिकोण, अनुपालन और लागू करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है, जो प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि भारत की 21वीं सदी की आकांक्षाएँ औपनिवेशिक शासन के पुराने तरीकों के माध्यम से पूरी नहीं हो सकतीं।

इस सुधार का पैमाना अभूतपूर्व है। जन विश्वास अधिनियम 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय कानूनों से जुड़े 784 प्रावधानों को संशोधित करता है। यह लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए 717 प्रावधानों को अपराधमुक्त करता है और 67 प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है। यह स्वतंत्र भारत के विधायी इतिहास में सबसे बड़ी अपराधमुक्ति पहल है।

यह 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाता है, पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाता है, पुराने औपनिवेशिक काल के अप्रचलित अपराधों को ख़त्म करता है और आपराधिक न्यायालयों के बाहर निर्णय और अपील की व्यवस्था को मजबूत करता है।

स्वागत योग्य बदलाव - पहले, किसी घर, इमारत या वाहन में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच मौजूद होने पर किसी व्यक्ति को तीन महीने की जेल हो सकती थी, यदि वह 'संतोषजनक स्पष्टीकरण' नहीं दे पाया हो। यह औपनिवेशिक काल के शक पर आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें सामान्य आवाजाही को भी संभावित अपराध माना जाता था। यह सुधार इस अपराध को पूरी तरह समाप्त कर देता है और कानून को आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है।

पिछली व्यवस्था के तहत, यदि किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस की समय-सीमा समाप्त हो गयी है, तो अगले ही दिन सड़क पर गाड़ी चलाने पर उस पर आपराधिक आरोप लग जाते थे। नए कानून में 30 दिन की छूट अवधि दी गई है।

एक छोटे निर्माता का उदाहरण लें, जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत पंजीकरण का विवरण अद्यतन नहीं कर पाता है। पहले यह एक आपराधिक चूक थी, लेकिन अब केवल नियमों की बार-बार अवहेलना पर ही सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

इसी तरह, पहले किसी खनन कंपनी की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में हुई चूक के कारण जेल की सज़ा तक हो सकती थी। आज, ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना लगता है। गैरकानूनी खनन, धोखाधड़ी, जानबूझकर नुकसान और सार्वजनिक हित के गंभीर उल्लंघनों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी अभी भी मौजूद है; लेकिन कागज़ी कार्रवाई की कमियों के लिए नहीं।

सभी के लिए 12 साल का लाभ - 'जन विश्वास' कानून, सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की पीएम मोदी के प्रयासों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के तौर पर देश-सेवा के 12 सालों में और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, यह पीएम मोदी का प्रमुख मिशन रहा है।

जन विश्वास 2026 एक महत्वपूर्ण स्तंभ पर आधारित है। भारत ने 2023 में पहले जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस प्रयास ने दिखाया कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को कमज़ोर किए बिना गैर-अपराधीकरण से शासन में सुधार किया जा सकता है। 2026 का कानून इस प्रक्रिया को लगभग चार गुना बढ़ा देता है, जो यह संकेत देता है कि यह कोई एक बार की पहल नहीं है, बल्कि सुधार की दिशा में लगातार चलने वाली पहल है।

बड़ा मिशन - नया कानून असल में पीएम मोदी के उस बड़े मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मिशन में, पीएम ने हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने की कोशिश की है और यह सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। यह कांग्रेस के शासनकाल से बिलकुल अलग है, जब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गए धन का सिर्फ़ 15% ही वास्तव में गरीबों तक पहुँचता है।

कम गंभीरता वाले आपराधिक प्रावधानों की जगह प्रशासनिक और मौद्रिक व्यवस्थाएँ लाना, न सिर्फ आम नागरिक के लिए स्वागतयोग्य कदम है, बल्कि यह छोटे व्यवसायों की भी मदद करता है। इससे लागू करने वाली एजेंसियां रोज़मर्रा की तकनीकी गलतियों के बजाय गंभीर उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अदालतें उन मामलों पर ध्यान दे सकती हैं, जिनमें सचमुच न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है।

अर्थव्यवस्था और निवेश - इसके फायदे सिर्फ़ शासन तक ही सीमित नहीं हैं। तेज़ी से प्रतिस्पर्धी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में, नियमों की विश्वसनीयता मायने रखती है। वर्षों तक, तकनीकी चूक के लिए आपराधिक मुक़दमे के डर को निवेश के सबसे बड़े रुकावटों में से एक माना जाता था। भारत में 2014 से 2025 के बीच एफडीआई में 143 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और एफडीआई बढ़ने का यह रुझान जारी है। इस विकास में नियामक सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका है। 'जन विश्वास 2026' का उद्देश्य भारत को निवेश और कारोबार के लिए ज़्यादा भरोसेमंद और अनुमान लगाने योग्य गंतव्य बनाकर इस रफ़्तार को और तेज करना है।

इस सुधार से न्याय प्रणाली को भी राहत मिलेगी। 5.5 करोड़ से ज़्यादा लंबित मामलों—जिनमें ज़िला और निचली अदालतों के लगभग 4.9 करोड़ मामले शामिल हैं— में से कई छोटे-मोटे नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं, जिन्हें अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे मामलों को प्रशासनिक निर्णय के लिए भेजना सिर्फ़ एक कारोबारी सुधार नहीं है, बल्कि एक न्यायिक सुधार भी है; इससे अदालतों को अपने सीमित समय और संसाधनों को गंभीर विवादों और न्याय से जुड़े अहम सवालों पर केंद्रित करने का मौका मिलता है।

गंभीर उल्लंघनों के लिए सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी। जहाँ सख़्ती ज़रूरी है, वहाँ कानून पूरी तरह सख़्त बना रहेगा। बदलाव सिर्फ दृष्टिकोण में आया है। शासन अब संदेह से विश्वास, अभियोजन से सुधार और डर से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है।

लेखक केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं

कमजोर मानसून का विकास दर पर असर

डॉ. जयन्तिलाल भंडारी

कमजोर मानसून और अल-नीनो के खतरे के पूर्वानुमान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खाद्य भंडारण को मजबूत करना होगा। भारत में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन एक 'सुरक्षा कवच' की तरह है।

आरबीआई द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर रहने से देश की कृषि और विकास दर पर असर पड़ सकता है। इस समय जून माह में समय से पीछे चल रहे मानसून ने खरीफ फसलों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी तक करीब 42 प्रतिशत बारिश कम होने से नकदी फसलें कपास और सोयाबीन बुवाई के आरंभिक दौर में पिछड़ गई हैं।

ऐसे में कृषि तथा अर्थव्यवस्था के सामने अल-नीनो और कमजोर मानसून से सूखे की आशंका तथा महंगाई की चुनौतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2026 में भारत अल-नीनो से अत्यधिक प्रभावित होगा। कमजोर मानसून और सूखे की स्थिति कृषि, जल आपूर्ति और महंगाई के परिदृश्य पर चुनौतियां निर्मित करते हुए दिखाई देगी।

इससे पहले वर्ष 2015 में भारत में अत्यधिक कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उस समय मानसून सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम था। इस वर्ष मानसून के दौरान अल-नीनो की स्थिति मजबूत होने की वजह से बारिश अत्यधिक कम होगी। इतना ही नहीं, जलाशयों के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। यह परिदृश्य भारत द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लक्षित विकास दर को बनाए रखने के लिए एक चुनौती दिखाई दे रहा है।

नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 प्रतिशत सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर है। सीडब्ल्यूएमआई के अनुसार, लगभग 74 प्रतिशत गेहूं और 65 प्रतिशत चावल की खेती वाले क्षेत्र पहले से ही भारी

जल-संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते रुझान से भारत में मानसून की वर्षा पर निर्भरता बढ़ी हुई है। मौजूदा परिदृश्य देश के वर्तमान सुकूनदायक कृषि क्षेत्र के समक्ष एक चुनौती बनकर दिखाई दे रहा है। कम बारिश से जलाशयों में पानी का स्तर गिरने से सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, ऐसे में अभी से जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए। भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढ़ना होगा।

कमजोर मानसून और अल-नीनो के खतरे के पूर्वानुमान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खाद्य भंडारण को मजबूत करना होगा। भारत में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन एक 'सुरक्षा कवच' की तरह है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था खाद्यान्न ताकत के कारण बहुत कम प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, कोरोना से जंग में देश के खाद्यान्न भंडार देश के लिए हथियार बन गए थे। इसलिए गेहूं के आगामी किसी भी नए निर्यात आदेश की पूर्ति के लिए सजगता रखनी होगी। चूंकि इस साल खरीफ सीजन की बुवाई शुरू से ही कम रहने से देश के किसानों और नीति-निर्माताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में पिछले 10 सालों का सबसे खराब और सूखा मानसून देखने को मिल सकता है। अल-नीनो के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून, 2026 से देशव्यापी 'खेत बचाओ' अभियान के तहत रणनीतिपूर्वक कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत किसानों को उनके इलाके और फसल के हिसाब से खास सलाह दी जा रही है, ताकि वे मौसम के जोखिमों को समझकर सही निर्णय ले सकें। इसके साथ-साथ किसानों को उनके इलाके के मौसम, वहां की मिट्टी और बाजार की मांग के हिसाब से कृषि उत्पादन संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

सरकार ने एक व्यापक और सहयोगी ढांचा तैयार किया है। इस अभियान में स्थानीय पंचायतों, राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और स्थानीय कृषि विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। कृषि मार्गदर्शन की पहुंच मजबूत करने के लिए 1,600 से ज्यादा विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें खेतों में जाकर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम-किसान जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद भी करेंगी। इसके साथ ही दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने, ऑयल पाम की खेती, कॉटन मिशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और जल संरक्षण जैसे अभियानों को भी इसी अभियान से जोड़कर जागरूकता फैलाई जाएगी।

लेखक अर्थशास्त्री हैं।

संपूर्ण दवा सुरक्षा शृंखला को कीजिए मजबूत

चंद्रकांत लहरिया

अधिकारियों को इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि सिर्फ़ बिक्री का तौर-तरीका बदलने से सुरक्षा की संपूर्ण शृंखला दुरुस्त हो जाएगी। असली काम एक ऐसी दवा प्रणाली बनाना है, जिसमें दवाएं उत्तम गुणवत्ता की हों, परामर्श तार्किक हों, दवा विक्रेता की ज़िम्मेदारी तय हो, नागरिक जानकारी युक्त हों और नियामक किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही कदम उठा लें।

अक्तूबर, 2025 में, मध्य प्रदेश के एक ज़िले में संदूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की ख़बरों ने देश को झकझोर दिया था। अब, जून, 2026 में, भारत सरकार ने कुछ नियम बदले हैं और 'शेड्यूल के' से सभी सिरप को अनुमति सूची से हटा दिया है। 'शेड्यूल के' में गांवों या ऐसी जगहों पर, जहां पर आबादी एक हज़ार से कम है, गैर-फार्मेसी दुकानों पर भी सिरप बिक्री को मंज़ूरी थी। अब पूरे देश में, दवा युक्त सिरप आम दुकानों पर नहीं रखी जा सकती और उनकी बिक्री डॉक्टर की पर्ची पर होना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी के बाद जांच हुई और कुछ नियामक पहल हुई। इस घटना की याद ने नीतिगत फैसले को आकार दिया है। हालांकि, इसे मोटे तौर पर कफ सिरप की बिक्री के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य किए जाने के फैसल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादातर दवा युक्त कफ सिरपों में (हर्बल सिरप को छोड़कर) ऐसे तत्व होते हैं, जिनकी खरीद या बेचने से पहले डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता हमेशा से थी। मगर, पालन नहीं किया जाता था।

यह नीतिगत फैसला स्पष्ट रूप से पर्ची की अनिवार्यता को सुदृढ़ करता है। सभी सिरपों में, भारत में सबसे अधिक गलत इस्तेमाल कफ सिरप का होता है। कई लोग बीमारी की सही शिनाख्त करवाए बिना खुद से इन्हें खरीद लेते हैं, छूत से लगी सर्दी-खांसी में इनका इस्तेमाल करते हैं जबकि इनसे फायदा बहुत कम होता है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद यह छोटे बच्चों को बार-बार खुराक दी जाती है। धारणा बना ली कि मीठा तरल नुकसानदायक प्रतीत नहीं होता। कुछ सिरप फार्मूलों में एंटीहिस्टामाइन, डिकंजेस्टेंट, सिडेटिव, ओपिओइड या अल्कोहल जैसे तत्व होते हैं, जो फायदे के बजाय नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं। किशोरों और वयस्कों में भी कुछ किस्म के सिरप का गलत इस्तेमाल होता है। पर्ची की अनिवार्यता बनने से लोग आसानी से इन्हें नहीं खरीद पाएंगे, पहले डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाएगा।

फिर भी, यह कहानी का सिर्फ़ एक हिस्सा है। कई परेशान माता-पिता के लिए बच्चे की खांसी चिंताजनक हो जाती है, और डॉक्टर के पास जाने पर अगर सिरप न लिखा जाए तो उन्हें अक्सर लगता है कि इलाज अधूरा रह गया। मरीज़ अक्सर कफ सिरप लिखने की मांग करते हैं और अगर डॉक्टर मना कर दे, तो कुछ परिवार किसी दूसरे डॉक्टर का रुख करते हैं, जो इसे लिख दे। पुरानी पर्चियों को भी संभालकर रखा जाता है और मिलते-जुलते लक्षणों के लिए वही दवा दोबारा खरीदने में इस्तेमाल किये जाते हैं। ऐसे हालात में, नियमों में यह बदलाव गलत इस्तेमाल को कम कर सकता है, पर्ची की अनिवार्यता होने को मजबूत करता है और गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को बदल सकता है।

बेशक, यह बदलाव स्वागतयोग्य है, लेकिन काफी नहीं है। मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी मुख्य रूप से डॉक्टर की पर्ची न होने के कारण नहीं हुई थी। यह बच्चों तक संदूषित उत्पाद पहुंचने के कारण हुई। जब डायथिलीन

ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल—वे औद्योगिक रसायन, जो दवाओं में कदापि नहीं होने चाहिए—किसी सिरप में मिला दिए जाएँ, तो यह व्यवस्था-तंत्र की विफलता है, जिसकी ज़िम्मेदारी ऊपर स्तर पर बैठे नियामकों की है। इसमें कच्चे माल की खरीद, परीक्षण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और बाज़ार से उत्पाद हटाने जैसी प्रक्रियाओं की प्रभावी निगरानी आवश्यक होती है। डॉक्टर की परामर्श पर्ची उपयोग को तो नियंत्रित कर सकती है, लेकिन संदूषित खेप को सुरक्षित नहीं बना सकती।

अन्य देश इस बाबत उपयोगी सबक हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, खांसी और जुकाम की कुछ दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के उपलब्ध हैं, लेकिन नियामक दो साल से कम उम्र के बच्चों में इनके उपयोग पर चेतावनी देते हैं, और निर्माता आमतौर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग के खिलाफ लेबल पर लिखा होता है। यूनाइटेड किंगडम में, कई खांसी और जुकाम की दवाएं छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं, जबकि छह से बारह वर्ष की आयु के बच्चों में उनका उपयोग स्वास्थ्य कर्मी की देख-रेख में होता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी छोटे बच्चों में इसके उपयोग को हतोत्साहित किया है और लेबल पर बाकायदा चेतावनी छापने को कड़ा कर रखा है। ये देश दुर्घटना अवसर घटाने के लिए केवल डॉक्टर की पर्ची पर निर्भर नहीं हैं। वे आयु प्रतिबंध, चेतावनी लेबल, डाक्टरी परामर्श, विष नियंत्रण प्रणाली, प्रतिकूल घटना पर त्वरित सूचना और निगरानी उपायों का उपयोग करते हैं।

भारत को एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाइयां न तो लिखी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए, सिवाय कुछ दुर्लभ मामलों में विशेषज्ञ की सलाह पर। इनसे बड़े बच्चों के लिए, मानकीकृत देखभाल की शुरुआत, दिलासा देने, तरल पदार्थ देकर, जरूरत पड़ने पर बुखार नियंत्रण, सेलाइन ड्रॉप्स, एक साल की उम्र के बाद शहद देना और स्पष्ट चेतावनी संकेतों को बूझना, जिन्हें चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता है, जैसे उपायों से हो सकती है। माता-पिता को यह पता होना चाहिए कि ज्यादातर खांसी एक संक्रमण रोग है, अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए सिरप की जरूरत नहीं होती।

दूसरा, उत्पादन नियमों को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। प्रत्येक पी जाने वाली दवा, जिसमें ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या सॉर्बिटोल जैसे सहायक पदार्थ शामिल होते हैं, उनकी विषाक्तता की अनिवार्य जांच की जानी चाहिए। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता लाइसेंस धारक हों, और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। राज्य औषधि नियामकों को प्रशिक्षित निरीक्षकों, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल रिकॉर्ड और दबाव से मुक्ति की आवश्यकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर केवल अस्थायी निलंबन ही नहीं, बल्कि मुकदमा और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए।

तीसरा, विषाक्ता का पता लगने पर शेष दवा को बाज़ार से तुरंत हटाने वाली प्रणाली होना जरूरी है। एक बार दूषित उत्पाद का संदेह होने पर, सूचना दिनों की बजाय घंटों में प्रसारित होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय डिजिटल दवा रिकॉल प्लेटफॉर्म हो, जोकि बैच नंबर, फार्मेसियों, डॉक्टरों, अस्पतालों और आम जनता से जुड़ा हो, इससे कई जानें बच सकती हैं। हर बोतल पर एक क्यूआर कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से माता-पिता निर्माता, बैच नंबर, समाप्ति तिथि और रिकॉल की स्थिति की पुष्टि कर सकें।

चौथा, डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। परामर्श पर्ची में बीमारी की शिनाख्त, उम्र के हिसाब से दवा की मात्रा और कितने समय तक दवा देनी है, यह सब दर्ज हो। खांसी की मिश्रित दवाएं (कॉम्बिनेशन सिरप) का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिए। दवा विक्रेताओं को बिक्री का रिकॉर्ड रखना चाहिए, तीमारदारों को जानकारी युक्त करना और असुरक्षित मांगों को साफ इंकार कर देना चाहिए। व्यावसायिक संस्थाओं को चाहिए कि आसानी से समझ आने वाली और व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी करें, जिनका पालन व्यस्त क्लीनिक और फार्मेसियों में किया जाना है।

आखिर में, समुदायों को भागीदार के तौर पर लिया जाना ज़रूरी है। आंगनवाड़ी कर्मी, 'आशा' कर्मी, स्कूल अध्यापक, बच्चों के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर और लोकल मीडिया तीन आसान बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं : छोटे बच्चों को खुद से तय करके दवा न दें; पुरानी सिरप पर्ची का दोबारा इस्तेमाल न करें। अगर किसी दवा सेवन के बाद बच्चे को पेशाब कम आए, लगातार उल्टी हो, सुस्ती छाए, सांस तेज़ चले या बीमारी और बढ़ जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पंचायतें और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 'सुरक्षित दवा दिवस' मना सकते हैं, जिनमें परिवार दवाइयों को सुरक्षित तरीके से जांचना, रखना और फेंकना सीख सकें।

अधिकारियों को इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि सिर्फ़ बिक्री का तौर-तरीका बदलने से सुरक्षा की संपूर्ण शृंखला दुरुस्त हो जाएगी। असली काम एक ऐसा दवा प्रणाली बनाना है जिसमें दवाएं उत्तम गुणवत्ता की हों, परामर्श तार्किक हों, दवा विक्रेता की ज़िम्मेदारी तय हो, नागरिक जानकारी युक्त हों और नियामक किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही कदम उठा लें। सवाल यह भी है कि क्या भारत घटना-आधारित उपाय करने से हटकर रोज़मर्रा की दवा-सुरक्षा की ओर बढ़ सकता है।

लेखक स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

कन्या महाविद्यालय की शिखा और तबस्सुम को पीएचडी

दुर्ग। शासकीय डॉ वावा पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गृहविज्ञान शोध केन्द्र की शिखा मरकाम को उनके शोध कार्य 'पर्सनैलिटी डाइमेंशन्स, स्कूल एनवायरनमेंट एंड डेमोग्राफिकल फैक्टर्स ऐज प्रेडिक्टर्स ऑफ करियर मैच्योरिटी' तथा तबस्सुम अली को उनके शोध कार्य 'सायकोलॉजिकल प्रेडिक्टर्स ऑफ इंटरनेट एडिक्शन अमोंग अडोलेसेन्ट्स' पर पीएचडी की उपाधि प्रदत्त की गई। उन्होंने अपना शोध कार्य शोध निर्देशक डॉ. रेशमा लाकेष के निर्देशन में पूरा किया। इनकी उपलब्धि पर प्राचार्य, डा रंजना श्रीवास्तव, गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अमिता सहगल, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. मीनाक्षी अग्रवाल, डॉ. किशन लाल राठी, डॉ. सुषमा यादव, डॉ. यशेश्वरी ध्रुव, डॉ. मोनिया राकेश एवं समस्त महाविद्यालय परिवार ने शिखा मरकाम और तबस्सुम अली को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

कुटेश्वर माइंस डिस्पेंसरी में नई डेंटल चेयर शुरू, मिलेगा लाभ

भिलाई। सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशिक किशोर के साथ कुटेश्वर माइंस का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कुटेश्वर चिकित्सालय और डिस्पेंसरी में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन कर सेवाओं के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कुटेश्वर डिस्पेंसरी में नवस्थापित डेंटल चेयर का उद्घाटन किया गया। निरीक्षण के समय रोगी सुविधाओं, स्वास्थ्य अधोसंरचना और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता पर चर्चा हुई। डॉ. ठाकुर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को लगातार मजबूत करना जरूरी है। बैठक में सेवाओं से जुड़ी चुनौतियों, आवश्यकताओं और सुधार की संभावनाओं पर भी विचार हुआ। कुटेश्वर माइंस की चिकित्सा टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. विनीता द्विवेदी और महाप्रबंधक मनोज कुमार मौजूद रहे।

निधन : रत्नकांता कोठारी

भिलाई। मकान 15/बी, सड़क-2, सेक्टर-2 निवासी 77 वर्षीय श्रीमती रत्नकांता कोठारी का निधन मंगलवार की शाम 6 बजे हो गया। उनकी अंतिम यात्रा 24 जून को शाम 4 बजे निवास से रामनगर मुक्तिधाम के लिए निकलेगी। वे महावीरचंद कोठारी की पत्नी, अशोक, विजय कोठारी की माता थीं।

चेतावनी-अपील बेअसर; सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब निगम की वक्र दृष्टि, लगाया भारी भरकम जुर्माना

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जोन-01 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड क्रमांक 04 कोसा नगर एवं वार्ड क्रमांक 17 आकाशगंगा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्रवाई की।

अभियान के दौरान सड़क पर सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया। इसमें मौर्या ट्रेडर्स पर 4 हजार रुपये, सतगुरू ट्रेडर्स पर 4 हजार रुपये तथा अभिषेक गुप्ता पर 2 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं भंडारण पाए जाने पर नंदकुमार साह से 1 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसी तरह सीएम पोर्टल के प्राप्त आवेदन के साथ वार्ड क्रमांक 18 कांट्रेक्टर कालोनी चौहान प्लाजा कॉम्प्लेक्स में संचालित आनंद गुप्ता द्वारा चाट सेंटर का संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण में सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास एवम् अनुज्ञप्ति लाइसेंस एवं साफ सफाई सही नहीं पाए जाने पर 7000 का चलानी कार्रवाई की गई। साथ ही बिना लाइसेंस के दुकान संचालित नहीं करने की समझाईश दी गई है।

इस प्रकार निगम की टीम ने कुल 18 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की। निगम अधिकारियों ने संबंधित व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में सड़क बाधा उत्पन्न करने या सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों एवं व्यापारियों से शहर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

बीएसपी प्रवर्तन विभाग ने अनाधिकृत कब्जों और सड़क अतिक्रमण के विरुद्ध छेड़ा विशेष अभियान

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग द्वारा टाउनशिप की स्वच्छता, यातायात सुगमता एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनाधिकृत कब्जों एवं अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सेक्टर-6 मार्केट चौक तथा आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान सेक्टर-6 मार्केट चौक के समीप सड़क पर पसरा लगाने वालों का अतिक्रमण हटया गया। छह अस्थायी शेड भी हटाए गए। संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में सड़क तक सामग्री न फैलाने तथा सार्वजनिक मार्गों को बाधित न करने की चेतावनी दी गई। एवेन्यू 'सी' स्थित अनफिट ब्लॉक में अवैध रूप से कब्जा कर रहने वाले व्यक्तियों के कारण मार्ग संकरा होने की स्थिति का भी संज्ञान लिया गया।

पूर्व में दिए गए निर्देशों एवं समझाइश के बावजूद कब्जा नहीं हटाए जाने पर नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के सहयोग से उक्त परिसर की अवैध विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गई। संबंधित कब्जाधारियों को पुन: निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र ही स्वेच्छा से कब्जा खाली करें। साथ ही संबंधित कार्यदल को उक्त ब्लॉक के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए गए।

इसी क्रम में सेंट्रल एवेन्यू से सेक्टर-6 मार्केट जाने वाले मार्ग तथा चौक क्षेत्र में दिन के समय ठेले खड़े छोड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई तथा ठेले हटवाए गए।

संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सार्वजनिक मार्गों पर ठेले छोड़ने की स्थिति में संपदा न्यायालय के माध्यम से जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

प्रवर्तन विभाग ने स्पष्ट किया है कि टाउनशिप के अन्य प्रमुख चौकों एवं मुख्य मार्गों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

नागरिकों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमण एवं अनाधिकृत रूप से रखे गए ठेले स्वेच्छा से हटा लें तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित टाउनशिप के निर्माण में सहयोग प्रदान करें।

यह विशेष अभियान भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के मार्गदर्शन में सहायक महाप्रबंधक (प्रवर्तन विभाग) रेमी थॉमस के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में प्रवर्तन विभाग के उप प्रबंधक मुकुंद दास मानिकपुरी, सहायक प्रबंधक देवानंद चौहान, संपदा निरीक्षक अजय मिश्रा, राममूर्ति, भगवान तथा राम सहित महिला एवं पुरुष सुरक्षा कर्मियों की टीम सक्रिय रूप से शामिल रही।

मोहर्रम की तैयारी : ताजिया निकलने के मार्गों से हटाई जा रहीं सड़क बाधाएं

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। मोहर्रम पर्व को ध्यान में रखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ताजिया जुलूस के लिए मोहल्लों, गलियों एवं मुख्य मार्गों पर झुकी हुई पेड़ों की डालियों की कटाई तथा मार्गों में लगे तोरण एवं अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य किया जा रहा है।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिया है कि मोहर्रम के मद्देनजर ताजिया मार्गों का निरीक्षण किया जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जुलूस मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निगम प्रशासन द्वारा सभी जोन में अमले की तैनाती कर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों को ताजिया मार्गों पर विशेष निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार शाखाओं की छंटाई, अवरोध हटाने एवं स्वच्छता कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीएसपी समूह खदानों में अधिकारियों के लिए प्रभावी नेतृत्व विकास कार्यशाला का आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-बीएसपी की समूह खदानों द्वारा अधिकारियों में प्रभावी नेतृत्व क्षमता विकसित करने तथा उन्हें बदलते कार्य परिवेश की चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजहरा में माइन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सेंटर (एमवीटीसी), दो दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय तेजी से हो रहे परिवर्तनों के दौर में टीम का नेतृत्व रखा गया था।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। संचालन सेल के पूर्व निदेशक (वाणिज्य) एवं प्रबंधन विशेषज्ञ डॉ. शोएब अहमद तथा नेतृत्व प्रशिक्षक एवं इमेज कंसल्टेंट आरती शर्मा द्वारा किया गया।

कार्यशाला के दौरान नेतृत्व कौशल, प्रभावी संचार, टीम निर्माण, परिवर्तन प्रबंधन, व्यक्तिगत प्रभावशीलता तथा संगठनात्मक उत्कृष्टता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को समूह गतिविधियों, केस स्टडी तथा संवादात्मक सत्रों के माध्यम से व्यावहारिक एवं अनुभवात्मक अधिगम का अवसर प्रदान किया गया।

अपने संबोधन में विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति उसके मानव संसाधन तथा नेतृत्व क्षमता में निहित होती है। बदलते कार्य परिवेश में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो टीमों को प्रेरित करने, विश्वास का वातावरण बनाने तथा चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करने में सक्षम हो।

इस अवसर पर प्रतिभागियों ने कार्यशाला को उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताते हुए इसकी सराहना की तथा प्राप्त सीख को अपने कार्यस्थल पर व्यवहारिक रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

भिलाई बचाने के लिए बलिदान भी दूंगा : देवेन्द्र

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर-9 अस्पताल, मैत्री बाग और भिलाई टाउनशिप की बसाहट को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि भिलाई केवल एक शहर नहीं, बल्कि देश की विविध संस्कृति, श्रमिकों के संघर्ष और पीढ़ियों की यादों का प्रतीक है। इसकी पहचान और बसाहट को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने दिया जाएगा।

मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व में हुए जनआंदोलन के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) प्रबंधन ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि सेक्टर-9 अस्पताल को न तो बेचा जाएगा और न ही किसी निजी संस्था को लीज पर दिया जाएगा।

इसी प्रकार मैत्री बाग और टाउनशिप की मूल बसाहट को भी सुरक्षित रखा जाएगा। यदि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इन परिसंपत्तियों को राज्य शासन को सौंपने पर विचार किया जाएगा। लेकिन छह माह बीत जाने के बाद भी बीएसपी प्रबंधन इस विषय पर कोई स्पष्ट पहल नहीं कर रहा है।

उन्होंने कहा कि लगातार संवाद और बैठक की मांग के बावजूद बीएसपी प्रबंधन

चर्चा से बच रहा है, जिससे लोगों के मन में आशंका और बढ़ गई है। टाउनशिप क्षेत्र के निवासियों को नोटिस दिए जाने की घटनाओं ने चिंता को और गहरा कर दिया है। डर है कि कहीं वर्षों पुरानी बसाहट को उजाड़ न दिया जाए।

विधायक ने कहा कि भिलाई की बसाहट को बचाने के लिए वे शुरू से संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी चर्चाएं भी सामने आ रही हैं कि सेक्टर क्षेत्र के बड़े हिस्से को खाली कराकर निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा।

देवेंद्र यादव ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता और औद्योगिक विकास की सोच के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी। भिलाई देश के विभिन्न राज्यों से आए लोगों की साझा संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे शहर की पहचान और बसाहट को समाप्त करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि पूरे भिलाई की है। भिलाई के हर नागरिक, कर्मचारी, श्रमिक और परिवार के भविष्य से यह मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी वर्गों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।

विधायक ने घोषणा की कि इस जनसंघर्ष की शुरुआत मीडिया के माध्यम से कर दी गई है। आने वाले दिनों में वे उन सभी परिवारों तक पहुंचेंगे जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे संवाद कर जनसमर्थन जुटाएंगे। यह आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा।

देवेंद्र यादव ने कहा, भिलाई की बसाहट हमारी पहचान है। इसे बचाने के लिए यदि मुझे अपना सर्वस्व अर्पित करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। भिलाईवासियों के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहूंगा।

बारिश से पहले महापौर ने नाली, पुलिया और सड़क निर्माण को दी गति

दुर्ग के वार्ड 24, 29 और 52 में विकास कार्यों का भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को गति देते हुए आज महापौर अलका बाघमार ने लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, शेखर चन्द्राकर, पार्षद बबिता गुड्डू यादव, पार्षद गुलशन साहू, पार्षद पायल पाटिल, रंजीता पाटिल, अनूप पाटिल, उपअभियंता अपर्णा मिश्रा, मंडल अध्यक्ष हरीश चौहान एवं बड़ी संख्या में उपस्थित वार्डवासियों के बीच विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।

इस दौरान वार्ड 29 अस्पताल वार्ड, वार्ड 24 आमदी मंदिर वार्ड तथा वार्ड 52 बोरसी क्षेत्र में नाली, पुलिया, सड़क सीमेंटीकरण एवं मुक्तिधाम जीर्णोद्धार आदि की आधारशिला रखी गई।

वार्ड 29 अस्पताल वार्ड में भागीरथ के घर से मदन यादव के घर तक विभिन्न स्थानों पर नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इसके अलावा सिद्धेश्वर शिव मंदिर से फरिस्ता कॉम्प्लेक्स, लाला जियो सेंटर होते हुए बबली कॉर्नर तक नाली निर्माण कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की गई। वहीं वार्ड क्रमांक 24 आमदी मंदिर वार्ड में भी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर नागरिकों को बेहतर जल निकासी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

कार्यक्रम के दौरान वार्ड 52 बोरसी स्थित मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार कार्य का भी विधिवत भूमिपूजन किया गया। इसके साथ ही डॉ. गोमास्ता के घर से एसडी विश्वकर्मा के घर तक सड़क सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य तथा महावीर खेल मैदान से बिजली ऑफिस होते हुए द्वारिकापुरी की ओर नाली निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। उपस्थित नागरिकों ने क्षेत्र में लंबे समय से अपेक्षित इन विकास कार्यों के लिए महापौर एवं निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि जल निकासी, सड़क, पुलिया एवं सार्वजनिक सुविधाओं के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है, ताकि लोगों को दैनिक जीवन में समस्याओं से राहत मिले।

कर्मचारी नगर में बच्चों-बुजुर्गों ने साथ-साथ किया योग का अभ्यास

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। कर्मचारी नगर में विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जागृति महिला समिति, आदर्श महिला समिति एवं नटराज फिटनेस एंड डांस अकैडमी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें कॉलोनी की महिलाओं एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई।

जागृति महिला समिति की अध्यक्ष सविता रजनीश वर्मा ने सभी महिलाओं से नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया।

आदर्श महिला समिति की अध्यक्ष इंदु ढोक ने विभिन्न योगासनों एवं उनके लाभों की जानकारी दी तथा सभी प्रतिभागियों को योग की सही विधि का अभ्यास कराया।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित 'अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना' के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 03 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित की गई है। जिला श्रम अधिकारी बालोद ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियो को प्रदेश के निजी स्कूलों में कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बालोद जिले को इस वित्तीय वर्ष मे 07 सीटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक निर्माणी श्रमिक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए 03 जुलाई 2026 तक ऑनलाईन आवेदन श्रमेव जयते मोबाइल एप्प के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा वे श्रम संसाधन केन्द्र गुण्डरदेही, गुरूर, बालोद, डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा या जिला श्रम कार्यालय बालोद के कक्ष क्रमांक 73 एवं 74 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर भी आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ निर्माण श्रमिक की प्रथम दो संतानो मिलेगा जिनका पंजीयन एक वर्ष पूर्व का हो तथा जो वर्तमान में शैक्षणिक सत्र कक्षा 6वीं में प्रवेश ले रहे हों।

आयुष्मान कार्ड अभियान में बलरामपुर ने हासिल की 92 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि

रायपुर। प्रदेश में नागरिकों को बेहतर और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। बलरामपुर जिले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से घर-घर पहुंचकर पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन एवं स्वास्थ्य मित्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को योजना से जोड़कर गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

शेडनेट हाउस ने बदली किसान की तकदीर

रायपुर। कभी परंपरागत खेती तक सीमित रहे बीजापुर जिले के ग्राम पोलेम के किसान कन्हैया आत्रम आज आधुनिक बागवानी तकनीक अपनाकर आर्थिक समृद्धि की नई मिसाल बन गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यानिकी विभाग के सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित किया, जिससे उनकी खेती की तस्वीर ही बदल गई। शेडनेट हाउस में कन्हैया आत्रम करेला, खीरा, तरोई और बरबटी जैसी सब्जियों की उन्नत खेती कर रहे हैं। उन्हें अब तक लगभग 2 लाख रुपये का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसमें सभी खर्च निकालने के बाद 1.80 लाख की शुद्ध आय हुई।

छत्तीसगढ़ में संवर रहा बचपनः 'बाल सक्षम नीति' के तहत बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए महाअभियान जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इसी कड़ी में प्रदेश के जिलों में 'बाल सक्षम नीति' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष और सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस दो महीने लंबे अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर जीवनयापन करने वाले, भिक्षावृत्ति में लिप्त और बाल श्रम जैसी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे बच्चों का स्थायी रेस्क्यू कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

कलेक्टर नारायणपुर के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से बाल सक्षम नीति अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नारायणपुर जिले के ग्राम गारपा, पांगुड, कोंगे, आकाबेडा और सोनपुर के साप्ताहिक बाजारों सहित विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेक्टर स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

प्रशासनिक टीमें लगातार सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, सामाजिक बैठकों और स्थानीय हाट-बाजारों का दौरा कर रही हैं। यहाँ ऐसे बच्चों (CNCP - देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे) की पहचान की जा रही है जो सड़क पर रहने या घूमने को मजबूर हैं। भिक्षावृत्ति या बाल श्रम में संलग्न तथा बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा से वंचित हैं। चिन्हित किए गए इन बच्चों को तत्काल आवश्यक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस अभियान का एक बड़ा हिस्सा जन-जागरूकता भी है। अधिकारियों के मुताबिक, सेक्टर बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों को 'मिशन वात्सल्य योजना' के अंतर्गत संचालित होने वाली गैर-संस्थागत सेवाओं और अन्य सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। ?ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को समझाया जा रहा है कि यदि कोई भी बच्चा संकटग्रस्त, असुरक्षित या शोषण की स्थिति में दिखे, तो उसकी अनदेखी करने के बजाय तुरंत संबंधित विभाग को 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन (बच्चों की सुरक्षा और रेस्क्यू के लिए) तथा 112 - आपातकालीन सेवा में सूचित करें।

मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर ने आम जनता से इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा सड़क पर रहने या काम करने के लिए मजबूर न हो, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आम नागरिक अपने आसपास के जरूरतमंद बच्चों की पहचान कर प्रशासन को सूचित करें, ताकि उन्हें समय पर सहायता मिल सके और इस महाअभियान को पूरी तरह सफल बनाया जा सके।

हर आंगन में समृद्धि की नई उम्मीदः समग्र डेयरी विकास योजना से बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

मंत्री रामविचार नेताम ने 13 पशुपालकों को सौंपी दुधारू गायें, कहा- कृपशुपालन बनेगा आत्मनिर्भर गांवों की सबसे बड़ी ताकत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिखने की दिशा में राज्य सरकार की समग्र डेयरी विकास योजना प्रभावी साबित हो रही है। इसी कड़ी में विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पचावल में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन तथा मछली पालन मंत्री श्री रामविचार नेताम ने 13 चयनित पशुपालकों को एक-एक दुधारू गाय, साइलेज पशुआहार एवं खनिज मिश्रण वितरित कर उनके जीवन में नई उम्मीदों का संचार किया।

इस अवसर पर मंत्री श्री नेताम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल पशु उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि पशुपालन आज किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का नहीं, बल्कि सम्मानजनक और स्थायी रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुका है।

मंत्री श्री नेताम ने बताया कि पहले दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ केवल आदिवासी समुदाय तक सीमित था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इसे सभी वर्गों के लिए लागू कर दिया है। इससे अब अधिक से अधिक ग्रामीण परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि समग्र डेयरी विकास योजना के तहत हितग्राहियों को केवल दुधारू गाय ही नहीं, बल्कि सफल डेयरी संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजना के अंतर्गत साइलेज, संतुलित पशु आहार, खनिज मिश्रण, एक वर्ष का पशु बीमा, पशु निगरानी उपकरण तथा वैज्ञानिक पशुपालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे पशुपालक आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अधिक उत्पादन और बेहतर आय अर्जित कर सकें।

मंत्री श्री नेताम ने पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में संचालित नियमित टीकाकरण, उपचार एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि स्वस्थ पशुधन ही डेयरी विकास की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने पशुपालकों से मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण कराने तथा वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने साइलेज के उपयोग और उसके लाभों की भी विस्तार से जानकारी दी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) डेयरी सर्विसेज के सहयोग से संचालित समग्र डेयरी विकास योजना के माध्यम से चयनित हितग्राहियों को अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर डेयरी व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। साथ ही दूध संग्रहण एवं विपणन की मजबूत व्यवस्था विकसित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा रही है। जिले में बड़ी संख्या में परिवार इस योजना से लाभान्वित होकर स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं।

ग्राम पचावल में दुधारू गाय प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के चेहरों पर झलकती खुशी इस बात का प्रमाण थी कि सरकारी योजनाएं जब सही हाथों तक पहुंचती हैं तो वे केवल सहायता नहीं देतीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को नई दिशा देती हैं। एक दुधारू गाय अब इन परिवारों के लिए नियमित आय, बच्चों की बेहतर शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मसम्मान का नया आधार बनेगी।

समग्र डेयरी विकास योजना ग्रामीण जीवन में समृद्धि, आत्मविश्वास और खुशहाली का नया अध्याय लिखती हुई दिखाई दे रही है। कार्यक्रम में एनडीडीबी के जोनल अधिकारी डॉ. आर.एच. पांडे, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण एवं बड़ी संख्या में पशुपालक उपस्थित थे।

धमतरी जिला प्रशासन की पहलः सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निपटारा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आम जनता की समस्याओं के समयबद्ध समाधान और सुशासन को धरातल पर प्रभावी बनाने के लिए धमतरी जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की नियमित और कड़ाई से समीक्षा की जा रही है। वर्तमान स्थिति 23 जून के अनुसार, जिले में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 835 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए 395 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण कर लिया गया है। शेष 440 शिकायतें वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार धमतरी जिले में शासकीय योजनाओं से जुड़े प्रमुख विभागों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सर्वाधिक 183 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 65 का निपटारा किया जा चुका है।?ऊर्जा विभाग में 141 शिकायतों में से 67 मामलों का समाधान किया गया है। इसी तरह ?राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त 128 शिकायतों में से 63 का निराकरण कर लिया गया है। ?खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 50 शिकायतों में से 40 का त्वरित निराकरण कर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

इसके साथ ही कृषि विकास, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा खनिज संसाधन विभाग द्वारा भी लंबित मामलों को सुलझाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में 324 शिकायतें ऐसी हैं जिनका निराकरण पूरा हो चुका है और आवेदकों से अंतिम फीडबैक लेना शेष है, जबकि 71 शिकायतों को पूर्ण रूप से क्लोज (निराकृत) कर दिया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर धमतरी श्री अबिनाश मिश्रा ने सभी जिला विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और नागरिकों के बीच सीधे संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है। सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता सूची में रखें और शिकायतकर्ताओं से सतत संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि आमजन की हर समस्या का समाधान पूरी संवेदनशीलता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ समय सीमा के भीतर किया जाए।

बिहान योजना से बदली उर्वशी बंजारे की तकदीर गृहणी से बनीं सफल उद्यमी और 'लखपति दीदी'

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम दे रही है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड की निवासी श्रीमती उर्वशी बंजारे इसकी एक प्रेरणादायी मिसाल हैं। कभी परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली उर्वशी आज सफल उद्यमी बनकर न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि ''लखपति दीदी'' के रूप में अपनी अलग पहचान भी स्थापित कर चुकी हैं।

अकलतरा जनपद अंतर्गत स्वतंत्र महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य उर्वशी बंजारे का परिवार पहले मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। सीमित आय और संसाधनों के कारण आर्थिक चुनौतियां बनी रहती थीं। इसी दौरान उन्होंने बिहान योजना से जुड़कर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नए अवसरों की तलाश शुरू की। योजना के तहत उनके समूह को प्रारंभिक रूप से 15 हजार रुपये की चक्रीय निधि तथा ग्राम संगठन के माध्यम से 60 हजार रुपये का सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त हुआ। बाद में बैंक लिंकेज के माध्यम से समूह को विभिन्न चरणों में ऋण सुविधा भी मिली। इस आर्थिक सहयोग और प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए उर्वशी ने ईंट निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय की सफलता के बाद उन्होंने एक फोटो कॉपी सेंटर भी स्थापित किया, जिससे उनकी आय के स्रोत और मजबूत हुए। शिक्षा और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी किया। लगातार मेहनत और योजनाबद्ध कार्य से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया। वर्तमान में वे ईंट निर्माण और फोटो कॉपी सेंटर के माध्यम से प्रतिमाह 12 से 15 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। उर्वशी बंजारे बिहान योजना के अंतर्गत अपने संकुल संगठन में एफएलसीआरपी (फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 6 हजार रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इस प्रकार उनकी कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो गई है और वे सफलतापूर्वक ''लखपति दीदी'' के रूप में स्थापित हुई हैं।

साय सरकार की पहल से उच्च शिक्षा का सपना होगा साकार, हजारों विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया शुरू

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा आर्थिक संबल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा। साय सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा न बने और हर युवा को अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो।

शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया 20 जून 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जबकि नवीन आवेदन 1 अगस्त 2026 से स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को समयबद्ध और सुव्यवस्थित बनाते हुए जनवरी 2027 तक छात्रवृत्ति राशि के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके और उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रहे।

योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालकों की वार्षिक आय सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पात्र विद्यार्थियों को आवेदन के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पूर्व वर्ष की अंकसूची एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बना रही है। इसी उद्देश्य से छात्रवृत्ति की राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाएगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा विद्यार्थियों को बिना किसी विलंब के राशि प्राप्त होगी।

वर्ष 2026-27 से छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) को अनिवार्य किया गया है। साथ ही नई संस्थाओं के संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी लागू की गई है।

यह कदम पात्र विद्यार्थियों तक योजनाओं का लाभ सही समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

सूरजपुर के जरही में 463 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से घर-घर पहुंचीं स्वास्थ्य सेवाएं, हजारों लोगों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना बनी शहरी गरीबों के लिए संजीवनी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजनामुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शहरी गरीब एवं स्लम बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में उभर रही है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सूरजपुर जिला के नगर पंचायत जरही में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों ने हजारों जरूरतमंद परिवारों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाकर जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत जरही में अब तक 463 स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 22,495 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया। प्रत्येक शिविर में औसतन 49 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। योजना के अंतर्गत 5,635 लैब जांचें की गईं तथा 19,395 मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को समय पर उपचार उपलब्ध हो सका।

गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान से बढ़ी स्वास्थ्य सुरक्षा

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत गैर-संचारी एवं गंभीर रोगों की शीघ्र पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में 536 नागरिकों की शुगर जांच की गई, जिनमें 86 मरीज मधुमेह से प्रभावित पाए गए। वहीं 21,603 लोगों का रक्तचाप परीक्षण किया गया, जिसमें 2,144 मरीज उच्च रक्तचाप एवं शुगर संबंधी समस्याओं से ग्रसित पाए गए। चिन्हित सभी मरीजों को आवश्यक उपचार, निःशुल्क दवाइयां एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया, जिससे रोगों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान और नियंत्रण संभव हो सका।

घर के पास स्वास्थ्य सुविधा से बढ़ा भरोसा

स्वास्थ्य शिविरों में नागरिकों को रक्तचाप परीक्षण, शुगर जांच, स्वास्थ्य परामर्श और आवश्यक उपचार जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे अस्पतालों तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों में कमी आई है और शहरी गरीब परिवारों को घर के समीप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से सूरजपुर जिले के जरही क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत हुई है। यह योजना न केवल लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करा रही है, और जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कोरियन फिल्म में काम करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनीं अनुष्का सेन

जेजू ओले में मिला ये किरदार...

एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने बड़ी अपलब्धि हासिल की है। वह साउथ कोरियन फिल्म में लीड रोल निभाने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बनने वाली हैं। 23 साल की यह स्टार आने वाली रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा जेजू ओले में लीड रोल निभाएंगी, जो भारत और साउथ कोरिया के बीच एक सांस्कृतिक सहयोग है।

फिल्म में अनुष्का ने अलीशा का किरदार निभाया है, जो अपनी बहन को खोने के दुख से उबरने की कोशिश करते हुए साउथ कोरिया के खूबसूरत जेजू आइलैंड पर पहुंचती है। जब वह अपनी भावनाओं को समझने और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करती है, तो उसका सिंगर-सॉन्गराइटर सुनवू (जिसे कोरियन एक्टर कांग ह्युंग-सेओक ने निभाया है) के साथ एक रिश्ता बन जाता है। फिल्म की कहानी जेजू आइलैंड की खूबसूरत लोकेशन पर आधारित है।

हाल ही में, अनुष्का ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से फिल्म में काम करने के अपने अनुभव, साउथ कोरिया के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव और एक नई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम के दौरान आई चुनौतियों के बारे में बात की।

इस प्रोजेक्ट के महत्व पर बात करते हुए, उन्होंने कहा कि जेजू ओले का महत्व इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि यह एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है, जिसे वह हमेशा से पसंद करती रही हैं।

अनुष्का ने बताया कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान के-ड्रामा देखना शुरू किया था। समय के साथ, उन्हें कोरियन कहानी कहने के अंदाज से प्यार हो गया और अक्सर वह ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का सपना देखती थीं।

उन्होंने कहा कि जेजू ओले जैसी फिल्म में लीड रोल निभाना, किसी सपने के सच होने जैसा है।

यह फिल्म कई जगहों के दर्शकों के लिए बनाई गई है और इसकी शूटिंग पूरे जेजू आइलैंड पर हुई है। फिलहाल, इसे साउथ कोरिया, भारत और कई अन्य एशियाई और मिडिल ईस्ट देशों में रिलीज करने की योजना है।

मेरे गाने आज भी लोगों को याद, संगीत बना सबसे खूबसूरत पहचान : करिश्मा कपूर

मनोरंजन की दुनिया में संगीत हमेशा से फिल्मों का अहम हिस्सा माना गया है। चाहे कहानी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर उसमें अच्छे गाने और संगीत जुड़ जाए, तो वह दर्शकों के बीच लंबे समय तक बना रहता है। इसको लेकर अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि उनके करियर की सबसे खूबसूरत पहचान वही गाने हैं, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। करिश्मा कपूर इन दिनों डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में जज के तौर पर नजर आ रही हैं।

उन्होंने बताया, इस शो में मुझे ऐसे अलग-अलग टैलेंट देखने को मिलते हैं, जो संगीत को अपने तरीके से पेश करते हैं। यह देखकर मुझे बेहद खुशी होती है कि आज के युवा सिर्फ गानों को सुनते ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी भावनाओं और डांस के जरिए एक नई कहानी में बदल भी देते हैं। यह बदलाव मुझे काफी प्रेरणादायक लगता है। करिश्मा कपूर ने कहा, मेरे लिए संगीत हमेशा से यादों, भावनाओं और एक खास जादू से जुड़ा रहा है। जब भी मैं इंडियाज बेस्ट डांसर 5 के सेट पर जाती हूं, तो यहां की परफॉर्मेंस देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। मुझे लगता है कि संगीत एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को किसी न किसी पल, भावना या समय से जोड़ देती है। एक अच्छा गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है और वह सीधे दिल तक पहुंचता है।

उन्होंने आगे कहा, मेरी फिल्मों की यात्रा में कई ऐसे गाने रहे हैं, जो आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। इन गानों ने न सिर्फ मुझे पहचान दी, बल्कि दर्शकों के दिलों में खास जगह भी दिलाई। एक कलाकार के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके काम को लोग सालों बाद भी याद रखें और उससे जुड़ाव महसूस करें। संगीत की ताकत यही है कि वह किसी भी इंसान को तुरंत पुराने समय में ले जा सकता है और बीती हुई यादों को फिर से जीवंत कर देता है।

अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, इंडियाज बेस्ट डांसर 5 में आने वाले प्रतिभागी जिस तरह से पुराने और नए गानों को मिलाकर परफॉर्म करते हैं, वह बेहद खास है। यह देखकर एहसास होता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और हर पीढ़ी इसे अपने तरीके से जीती है।

करिश्मा कपूर ने दिल तो पागल है फिल्म के शूटिंग के दिनों को याद किया और बताया कि इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ी थी। इस दौरान उन्होंने डांस और परफॉर्मेंस की बारीकियों को और बेहतर तरीके से समझा।

हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का टीजर जारी, एक्शन-रोमांच से है भरपूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पिछले कुछ समय से अपनी एक अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का नाम है'बेबी डू डाई डू', जो 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब मेकर्स ने इस फिल्म का एक टीजर वीडियो जारी कर दिया है। टीजर वीडियो में हुमा कुरैशी एक किलर के किरदार में नजर आ रही हैं। टीजर को देखकर कहानी के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुमा का किरदार अपनी बहन की मौत का बदलने लेने के लिए लोगों का मर्डर कर रही है। टीजर की शुरुआत एक लड़की के वॉयसओवर से होती है।

वो कहती है, ये कहानी उस रात शुरू होती है जिस रात मेरा मर्डर हुआ था, लेकिन ये स्टोरी मेरे बारे में नहीं है। ये मेरी गूंगी-बहरी बहन की कहानी है। उसके बाद हुमा कुरैशी के किरदार के एंट्री होती है, जो एक के बाद एक लोगों का मर्डर करती है। वो बोल और सुन नहीं सकती है। शहर में उसका खौफ फैल जाता है। वो हमेशा अपने साथ एक छाता लेकर चलती है। नचिकेत सामंत ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और हुमा के भाई साकिब सलीम इसके प्रोड्यूसर हैं। चंकी पांडे भी इस पिक्चर में नजर आने वाले हैं। टीजर में एक जगह पर उनकी छोटी सी झलक दिखी है।

रोलर स्केटिंग सीखने की सोच रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

रोलर स्केटिंग एक मजेदार और रोमांचक गतिविधि है। यह न केवल आपको फिट रखती है, बल्कि आपके संतुलन को भी सुधारती है। अगर आप रोलर स्केटिंग सीखने की सोच रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जो आपको रोलर स्केटिंग में मदद करेंगे। सही जूते चुनें, सुरक्षा उपकरण पहनें, सही तरीके सीखें, नियमित अभ्यास करें और संतुलन बनाए रखें जैसे महत्वपूर्ण सुझावों पर ध्यान दें।

सही जूते चुनें

रोलर स्केटिंग के लिए सही जूते का चयन करना बहुत जरूरी है। जूते आरामदायक होने चाहिए ताकि आप लंबे समय तक स्केटिंग कर सकें। इसके अलावा जूतों का आकार और फिटिंग भी सही होनी चाहिए ताकि आपका पैर सही तरीके से जूते में फंसे और फिसले नहीं। अच्छी गुणवत्ता वाले जूते खरीदें जो आपके पैरों को सही सपोर्ट दें और आपको स्केटिंग में मदद करें। ध्यान रखें कि जूतों का तलवा चिकना होना चाहिए ताकि फिसलन बनी रहे।

सुरक्षा उपकरण पहनें

रोलर स्केटिंग करते समय सुरक्षा उपकरण पहनना बहुत जरूरी है। सिर पर टोपी, घुटनों पर पैड, कोहनियों पर पैड और कलाई पर गार्ड्स पहनें ताकि अगर गिरते हैं तो चोट कम लगेगी। इन उपकरणों से आप सुरक्षित रहेंगे और आत्मविश्वास के साथ स्केटिंग कर सकेंगे। बच्चों को खासतौर पर सुरक्षा उपकरण पहनाने पर जोर दें ताकि वे भी सुरक्षित रहें और बिना किसी डर के स्केटिंग का आनंद ले सकें। सुरक्षा उपकरण पहनकर आप अधिक आराम महसूस करेंगे।

सही तरीके सीखें

रोलर स्केटिंग सीखते समय सही तरीके बहुत अहम होते हैं। पहले संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें, फिर धीरे-धीरे गति बढ़ाएं। हाथों को संतुलन बनाए रखने के लिए खुला रखें और घुटनों को थोड़ा मोड़कर रखें ताकि फिसलन बनी रहे। इसके अलावा मुड़ते समय शरीर को हल्का झुकाएं ताकि मोड़ आसानी से कट सके। नियमित अभ्यास से आप इन तरीकों में माहिर हो सकते हैं और रोलर स्केटिंग का पूरा मजा ले सकते हैं।

नियमित अभ्यास करें

रोलर स्केटिंग में माहिर बनने के लिए नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। रोजाना कुछ समय निकालकर स्केटिंग करें और अपनी गलतियों से सीखें। धीरे-धीरे आपकी स्केटिंग में सुधार होगा और आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इसके अलावा अलग-अलग सतहों पर स्केटिंग करने की कोशिश करें ताकि आप हर तरह के माहौल में सहज हो सकें। इससे आपकी तकनीक और संतुलन दोनों बेहतर होंगे और आप रोलर स्केटिंग का पूरा मजा ले सकेंगे।

संतुलन बनाए रखें

संतुलन बनाए रखना रोलर स्केटिंग का सबसे अहम हिस्सा है। हमेशा अपने वजन को दोनों पैरों पर बराबर रखें और घुटनों को थोड़ा मोड़कर रखें ताकि फिसलन बनी रहे। इसके अलावा हाथों को खुला रखें ताकि संतुलन बनाए रखना आसान हो। इन सरल टिप्स को अपनाकर आप रोलर स्केटिंग सीख सकते हैं और इसका पूरा मजा ले सकते हैं। याद रखें कि किसी भी नई गतिविधि को सीखने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और नियमित अभ्यास करें।

घर की सफाई को आसान बना सकते हैं ये एसेंशियल ऑयल, ऐसे करें इस्तेमाल

घर की सफाई के लिए अक्सर हम महंगे और केमिकल युक्त क्लीनर का सहारा लेते हैं, जो न केवल महंगे होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में कुछ आवश्यक तेलों का उपयोग करके घर की सफाई करना न केवल सस्ता हो सकता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर है। आइए जानते हैं कि किन-किन एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग घर की सफाई के लिए किया जा सकता है।

नींबू का तेल

नींबू का तेल एक बहुत अच्छा आवश्यक तेल है, जो आपके घर को ताजगी भरा बना सकता है। इसे आप फर्श पर पोछा लगाने के लिए या दीवारों और फर्नीचर की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह कीटाणुओं को भी नष्ट करता है और एक सुखद खुशबू छोड़ता है। नींबू के तेल को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से सफाई भी बेहतर होती है और घर की हवा भी ताजगी भरी लगती है।

लैवेंडर का तेल

लैवेंडर का तेल न केवल घर को साफ रखता है बल्कि एक आरामदायक खुशबू भी देता है। इसे आप बाथरूम या रसोई में छिड़क सकते हैं ताकि कीटाणु खत्म हों और बदबू दूर हो जाए। इसके अलावा यह तेल आपके मन को शांत करता है और तनाव को दूर करता है। लैवेंडर के तेल का उपयोग करने से आपके घर का माहौल भी ताजगी भरा और आरामदायक बन जाता है, जिससे आप और आपका परिवार खुश रहते हैं।

टी ट्री का तेल

टी ट्री का तेल एक असरदार आवश्यक तेल है, जो बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने में मदद करता है। इसे आप अपने कपड़ों के धोने वाले पानी में डाल सकते हैं या फिर पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। यह न केवल कपड़ों को साफ करता है बल्कि गंदगी और कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। इसके अलावा यह आपके कपड़ों को ताजगी भरी खुशबू भी देता है, जिससे आपका धुलाई का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है।

पुदीना का तेल

पुदीना का तेल एक ताजगी भरा आवश्यक तेल है, जो आपके घर की हवा को ताजगी भरी बना सकता है। इसे आप कचरा पेटी या फ्रिज में छिड़क सकते हैं ताकि बदबू दूर हो जाए। इसके अलावा इसे आप फर्श पर पोछा लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना का तेल का उपयोग करने से आपके घर का माहौल भी ताजगी भरा और आरामदायक बन जाता है, जिससे आप और आपका परिवार खुश रहता है।

रोजमेरी का तेल

रोजमेरी का तेल एक आवश्यक तेल है, जो कीटाणुओं को मारने और ताजगी देने में मदद करता है। इसे आप रसोई के कटिंग बोर्ड आदि की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बैक्टीरिया नष्ट हों और बदबू दूर हो जाए। इन आवश्यक तेलों का उपयोग करके आप अपने घर को न केवल साफ-सुथरा रख सकते हैं बल्कि प्राकृतिक रूप से ताजगी भी दे सकते हैं। इनसे आपका घर खुशबूदार रहेगा और सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा।

खास खबर

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए आवेदन 31 जुलाई तक

रायपुर। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों तथा कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2026 को प्रदान किए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं 31 जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कारों के माध्यम से उन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। इनमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पुनर्वास सेवाएं, कौशल एवं दक्षता विकास, रोजगार सृजन, सुगम्यता को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं नवाचार, खेल, कला, साहित्य तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां और योगदान शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग ने पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों से निर्धारित समयावधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

आधुनिक खेती और नैनो उर्वरक से किसान लक्ष्मी सोढ़ी ने बढ़ाई पैदावार

रायपुर । कोंडागांव जिले के ग्राम उमरगांव के किसान लक्ष्मी सोढ़ी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाते हुए शासन की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खेती में बेहतर उत्पादन और आय अर्जित कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने वैज्ञानिक खेती और नैनो उर्वरकों के उपयोग से यह साबित कर दिया है कि नई तकनीकें किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। श्री लक्ष्मी सोढ़ी के पास कुल चार एकड़ कृषि भूमि है। इनमें से दो एकड़ भूमि में वे धान की खेती करते हैं, जबकि शेष दो एकड़ टिकरा भूमि में मक्का एवं अन्य फसलें लगाते हैं। उन्होंने बताया कि पहले वे पारंपरिक पद्धति से खेती करते थे, जिससे उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था और लागत के अनुपात में पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता था। समय के साथ कृषि विभाग के मार्गदर्शन और आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिलने पर उन्होंने खेती के तौर-तरीकों में बदलाव किया। लक्ष्मी सोढ़ी ने अपनी फसलों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग शुरू किया। उनका कहना है कि नैनो उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की वृद्धि बेहतर हुई है तथा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। कम मात्रा में उपयोग होने के बावजूद यह फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जिससे खेती की लागत में कमी आती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी उन्हें नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से कृषि कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में मदद मिलती है तथा खेती की लागत का कुछ भार कम होता है।

राज्य डेटा सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूतीः उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला

डिजिटल गवर्नेंस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर जोर, देशभर के विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य में डिजिटल गवर्नेंस के तेजी से बढ़ते दायरे और शासकीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच नागरिकों के डेटा एवं महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से रायपुर में **"Strengthening Cyber Security Frameworks for State Data"** विषय पर राज्य स्तरीय विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा चिप्स द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों के 120 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और राष्ट्रीय स्तर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनन्द ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस की सफलता नागरिकों के विश्वास पर आधारित है और यह विश्वास तभी मजबूत होगा जब शासकीय डिजिटल प्रणालियां सुरक्षित, विश्वसनीय और साइबर खतरों का सामना करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह सुशासन, सेवा निरंतरता और जनविश्वास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विषय बन चुका है। राज्य शासन का लक्ष्य केवल डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित और लचीला बनाना भी है।

चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य शासन साइबर सुरक्षा को डिजिटल शासन की आधारशिला मानते हुए राज्य की डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यापक और भविष्य उन्मुख रोडमैप तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छह प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें जोखिम आधारित सुरक्षा मूल्यांकन, राज्य डेटा सेंटर एवं नेटवर्क सुरक्षा, सुरक्षा संचालन केंद्र , जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, डेटा गवर्नेंस तथा साइबर जागरूकता एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।

तकनीकी सत्रों में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर विस्तृत जानकारी साझा की। पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएं) डॉ. ध्रुव गुप्ता ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून वर्ष 2027 से पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को छह विषयगत समूहों में विभाजित कर विस्तृत विचार-विमर्श कराया गया। चर्चा के दौरान साइबर सुरक्षा परिपक्वता बढ़ाने, सुरक्षा निगरानी तंत्र को मजबूत करने, विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने, नियमित सुरक्षा ऑडिट, प्रभावी घटना प्रतिक्रिया तंत्र और मानव संसाधन क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए।

कार्यशाला से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं का संकलन कर राज्य की साइबर सुरक्षा कार्ययोजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। चयनित अनुशंसाओं को राष्ट्रीय स्तर पर विचारार्थ संबंधित संस्थाओं एवं भारत सरकार को भी भेजा जाएगा। कार्यक्रम में एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. व्ही. रमन्ना राव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी टी.एन. सिंह, चिप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, यू.एस. अग्रवाल, आशीष जायसवाल, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपम आशीष टोप्पो सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने सुरक्षित डिजिटल शासन, मजबूत साइबर अवसंरचना तथा नागरिकों के डेटा संरक्षण के लिए सभी विभागों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। यह कार्यशाला राज्य में साइबर सुरक्षा को नई दिशा देने और डिजिटल सेवाओं को अधिक सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।

बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए गांव-गांव पहुंच रही बाल चौपाल

सपेरा बस्ती में आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बच्चों को किया जागरूक, गुड टच-बैड टच की दी जानकारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके समग्र विकास और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम भीखमपुरा स्थित सपेरा बस्ती में बाल चौपाल का आयोजन कर बच्चों और अभिभावकों से सीधा संवाद किया। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण एवं वंचित समुदायों तक बाल संरक्षण और जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले के प्रवास के दौरान आयोजित इस बाल चौपाल में डॉ. शर्मा ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक एवं सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक वातावरण प्राप्त होना उसका मौलिक अधिकार है तथा समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के हितों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. शर्मा ने विशेष रूप से बालिकाओं और बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में सरल और प्रभावी तरीके से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने, किसी भी अनुचित व्यवहार या गतिविधि की जानकारी तत्काल अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही बच्चों को शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बाल चौपाल में बच्चों की प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। संस्कृति, लोककला और पारंपरिक कलाओं में रुचि रखने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। आयोग अध्यक्ष ने बच्चों और उनके अभिभावकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की जानकारी ली तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर डॉ. शर्मा ने बाल विवाह, बाल श्रम और नशीले पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति को बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए इन सामाजिक बुराइयों से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए शासन, प्रशासन, समाज और परिवारों को मिलकर कार्य करना होगा।

नैनो उर्वरकों से बढ़ रही फसलों की उत्पादकता मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को भी मिल रहा बढ़ावा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों और नवाचारों के बढ़ते उपयोग से किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के नए अवसर मिल रहे हैं। नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी जैसे उन्नत उर्वरक खेती को अधिक लाभकारी बनाने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के किसान अब आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए टिकाऊ एवं संतुलित खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम मेंड्राखुर्द के प्रगतिशील किसान श्री नैहर साय ने नैनो उर्वरकों के उपयोग को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने से उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कृषि भूमि की गुणवत्ता को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। धान एवं सब्जी उत्पादन से जुड़े श्री नैहर साय का मानना है कि खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक दानेदार उर्वरकों के अत्यधिक एवं असंतुलित उपयोग से समय के साथ मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे उर्वरक पोषक तत्वों को अधिक प्रभावी ढंग से पौधों तक पहुंचाने में सक्षम हैं, जिससे फसलों की वृद्धि और उत्पादन क्षमता में सकारात्मक सुधार देखने को मिलता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नैनो उर्वरकों का उपयोग पर्णीय छिड़काव के माध्यम से किया जाता है, जिससे पोषक तत्व सीधे पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं।

डीएमएफ निधि से खनिज प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं को मिलेगी प्राथमिकता

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। परिषद की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में डीएमएफ अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय राशि, प्रगतिरत कार्यों तथा विभिन्न नए प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। परिषद ने निर्णय लिया कि डीएमएफ निधि का उपयोग निर्धारित कार्ययोजनाओं के अनुरूप खनिज प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए किया जाएगा।

बैठक में सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक ब्यास कश्यप, राघवेंद्र कुमार सिंह, बालेश्वर साहू, शेषराज हरबंश, जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी, कलेक्टर जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय, डीएफओ श्री हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे सहित शासी परिषद के सदस्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत तैयार की गई पांच वर्षीय निधि आबंटन योजना के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, आवास, सिंचाई, ऊर्जा एवं आधारभूत अधोसंरचना विकास जैसे क्षेत्रों में डीएमएफ निधि का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खनन प्रभावित क्षेत्रों में निजी सहभागिता एवं आंशिक वित्तपोषण के माध्यम से व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से जनकल्याणकारी एवं विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं परिषद सदस्यों ने खनिज प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने डीएमएफमद से स्वीकृत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने तथा निधि का उपयोग जिले के संतुलित एवं सतत विकास के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

सदस्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, सड़क एवं पेयजल सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा अन्य जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता देने के सुझाव दिए, ताकि खनिज प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके।

अनियमितताएं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई

स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर राज्य सरकार का सख्त, पेंड्रा रोड के डीडी हॉस्पिटल को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार सतर्क और सक्रिय है। इसी कड़ी में जीपीएम जिला प्रशासन के निर्देश पर डी.डी. हॉस्पिटल, सेमरा तिराहा पेंड्रारोड का स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत निरीक्षण एवं जांच की गई। जांच के दौरान अस्पताल के संचालन तथा मरीजों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जांच में सामने आया कि मृतक मरीज ज्योति सोनवानी एक्लेम्सिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसका उपचार चिकित्सा महाविद्यालय स्तर की स्वास्थ्य संस्था में किया जाना आवश्यक था। इसके बावजूद मरीज को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किए जाने को नियमानुसार उचित नहीं पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है।

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नर्सिंग होम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपातकालीन सेवाओं के लिए चौबीसों घंटे चिकित्सक की उपलब्धता अनिवार्य है, किंतु 17 एवं 18 जून 2026 को अस्पताल में मरीजों की देखरेख के लिए कोई चिकित्सक एवं पर्याप्त दक्ष स्टाफउपलब्ध नहीं था। यह स्थिति न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि मरीजों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया, जहां सर्जरी के बाद कई मरीज भर्ती पाए गए। ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में ऑन ड्यूटी चिकित्सक का अनुपस्थित होना अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। जांच में यह भी सामने आया कि शल्य चिकित्सा कार्यों के लिए आवश्यक स्त्री रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ तथा अन्य प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। साथ ही भर्ती मरीजों की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए आवासीय चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था भी नहीं पाई गई।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों से निर्धारित पैकेज के अतिरिक्त लगभग एक लाख पचास हजार रुपये की राशि लिए जाने संबंधी शिकायत भी जांच के दौरान सामने आई। स्वास्थ्य विभाग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच प्रारंभ कर दी है। प्रशासन का स्पष्ट मत है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के पहुंचना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अस्पताल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के अंतर्गत निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। अस्पताल प्रबंधन को तीन दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों के जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के मार्गदर्शन में जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं की नियमित निगरानी जारी रहेगी तथा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मिली नई गति 106 बल्क वेस्ट जनरेटर पंजीकृत

रायपुर। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने बिलासपुर जिले में अब तक 106 बल्क वेस्ट जनरेटर का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया है। ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा स्वच्छ एवं सतत विकास के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में जिले की इस पहल को अहम कदम माना जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिलासपुर जिले में बड़ी संख्या में बल्क वेस्ट जनरेटर के पंजीयन पर कहा कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

रेत से भरा ट्रैक्टर और ट्रॉली जब्त, चालक जंगल से फरार

बिजुरी। बिजुरी पुलिस ने रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की। ग्राम मझौली में बिना अनुमति रेत ले जाते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस की घेराबंदी देखकर चालक वाहन छोड़कर पास के जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक मझौली में अवैध रेत परिवहन की सूचना मिली थी। टीम ने मझौली मुख्य सड़क पर घेराबंदी की। इसी दौरान लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर आता दिखा। पुलिस सामने दिखी तो चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर खड़ा कर जंगल की तरफभाग निकला। पुलिस ने पीछा किया। आरोपी हाथ नहीं आया। पुलिस ने गवाहों के सामने अवैध रेत से लदा ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किया। इसकी कीमत करीब 5 लाख 5 हजार रुपए आंकी गई।

महुआ बीनने गई बुजुर्ग महिला पर लोनर हाथी का हमला, मौके पर मौत

कोरबा। कटघोरा वन मंडल के केंदई वन परिक्षेत्र के ग्राम पतुरियाडांड़ में एक दर्दनाक घटना में लोनर हाथी ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। सुखमत बाई (70 वर्ष), पति लोडुराम, रोज की तरह जंगल में महुआ डोरी बीनने गई थीं। इन दिनों जंगलों में महुआ के फल गिर रहे हैं, जिन्हें ग्रामीण तेल निकालने सहित अन्य घरेलू उपयोग के लिए एकत्र करते हैं। इसी दौरान अचानक एक लोनर हाथी सामने आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाथी को देखकर बुजुर्ग महिला ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच सकीं। हाथी ने उन पर हमला कर उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं, जनपद सदस्य और ग्राम सरपंच की मौजूदगी में मृतका के परिजनों को 25 हजार रुपये की तत्काल राहत सहायता प्रदान की गई।

अमाबगीचा में जुए के फड़ पर धमतरी पुलिस की दबिश, 8 जुआरी गिरफ्तार

धमतरी। धमतरी पुलिस ने अवैध जुआ-सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भखारा क्षेत्र के ग्राम रामपुर स्थित अमाबगीचा में चल रहे जुए के फड़ पर छापेमार कार्रवाई कर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। थाना भखारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रामपुर के अमाबगीचा में कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कार्रवाई की। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे 8 व्यक्तियों को मौके से पकड़ा गया। पूछताछ में उनकी पहचान मेघनाथ साहू, राजेश कुमार रात्रे, महादेव रात्रे, गजेंद्र कुमार निषाद, नारदराम निषाद, छन्नु लाल रात्रे, देनेश्वर साहू एवं कवल सिंह साहू के रूप में हुई। सभी आरोपी ग्राम रामपुर, थाना भखारा, जिला धमतरी के निवासी हैं।

यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 बसों समेत कई वाहनों पर कार्रवाई

बिलासपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बिलासपुर यातायात पुलिस ने सोमवार को सख्त अभियान चलाते हुए 20 बसों समेत कई अन्य वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और अमानक हूटर हटाए गए तथा चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में चलाए गए इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान जिन वाहनों में प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगे पाए गए, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। गंभीर मामलों में प्रकरण तैयार कर न्यायालय भी भेजे गए हैं।

इथेनॉल प्लांट के नाम पर 1.48 करोड़ की ठगी

फर्जी इनवॉयस देकर कंपनी से लिए पैसे, लेकिन सामान नहीं दिया, दिल्ली की कंपनी पर एफआईआर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बन रहे इथेनॉल प्लांट के लिए सामान खरीदने के नाम पर 1 करोड़ 48 लाख 50 हजार रुपए की ठगी की गई है। आरोप है कि दिल्ली की कंपनी ने फर्जी बिल (इनवॉयस) देकर रकम ले ली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कंपनी संचालक के खिलाफमामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एआई इमेज

मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम राकेश प्रकाश पांडेय (59) है, जो सिद्धि विनायक कॉलोनी, इंदिरा नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे साल 2004 से ग्राम सराईपाली स्थित नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर हैं। कंपनी के संचालक ओडिशा के राजगांगपुर निवासी दीपक शर्मा हैं।

साल 2024 में कंपनी की ओर से 100केएलपीडी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा था। इसके लिए 75 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले ग्रेन स्टोरेज साइलो की आवश्यकता थी। सामान खरीदने के लिए कंपनी ने दिल्ली की Ben and Gaws Pvt. Ltd. से संपर्क किया। यह संपर्क कंपनी के कंसल्टेंट सुखराज सोनी के माध्यम से हुआ, जो इथेनॉल प्लांट परियोजना में सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कम कीमत पर सामान मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया था। दोनों कंपनियों के बीच शर्तों पर सहमति बनने के बाद 20 अप्रैल 2024 को परचेज ऑर्डर जारी किया गया। इसमें 75 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले दो साइलो खरीदने का सौदा तय हुआ। सामान की कीमत 2 करोड़ 97 लाख रुपए थी। सामान की सप्लाई के लिए नवदुर्गा फ्यूल कंपनी ने अलग-अलग तारीखों में आरजीटीएस के जरिए कुल 2 करोड़ 17 लाख 55 हजार 265 रुपए का भुगतान किया। इसके बदले कंपनी ने 20 दिसंबर 2024 को केवल 68 लाख 90 हजार 400 रुपए का ही सामान भेजा।

बाकी सामान के लिए कंपनी ने 1 करोड़ 48 लाख 50 हजार रुपए का बिल (इनवॉयस) जारी कर यह दावा किया कि पूरा माल भेज दिया गया है, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी सामान नहीं पहुंचा। इससे कंपनी पर फर्जी बिल देकर गुमराह करने का आरोप लगा।

संदेह होने पर कंपनी के अधिकारियों ने संचालक द्विपायन दत्ता से संपर्क किया। उन्होंने 2 महीने के भीतर पूरा सामान भेजने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी वह लगातार टालमटोल करता रहा और ई-मेल के जरिए फर्जी डिस्पैच दस्तावेज भेजता रहा।

1.48 करोड़ का चेक भी हुआ बाउंस

माल नहीं मिलने पर 29 दिसंबर 2024 को कंपनी के कर्मचारी मोहित कुमार को हरियाणा स्थित कंपनी कार्यालय भेजा गया। वहां सामान मुहैया नहीं करा पाने की स्थिति में कंपनी ने 1 करोड़ 48 लाख 44 हजार 160 रुपए का चेक दिया। जब यह चेक बंधन बैंक, बदरपुर (दिल्ली) में जमा कराया गया तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।

पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

चेक बाउंस होने और सामान नहीं मिलने के बाद नवदुर्गा फ्यूल कंपनी के अधिकारियों को धोखाधड़ी का संदेह हुआ। इसके बाद राकेश प्रकाश पांडेय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पूंजीपथरा थाना पुलिस ने Ben and Gaws Pvt.Ltd. के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नक्सल डंप का भंडाफोड़, पुलिस व बीएसएफ की कार्रवाई में हथियारों का जखीरा बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिसव बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई। यह कार्रवाई मंगलवार को थाना छोटेबेठिया, जिला कांकेर के ग्राम आमाटोला के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए सघन सर्चिंग अभियान के दौरान यह नक्सल डंप मिला।

डंप से कई महत्वपूर्ण नक्सल सामग्री और हथियार बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान चार भरमार बंदूकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दो वायरलेस सेट भी मिले हैं। एक रेडियो भी बरामद किया गया है। एक नक्सल वर्दी और दो पोच भी जब्त किए गए। एक चार्जर और एक बैटरी भी मिली है। नक्सल साहित्य के साथ अन्य कई सामग्री भी बरामद हुई।

कांकेर पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार संयुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। यह कार्रवाई जिला पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने की है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा बल लगातार सघन सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। कांकेर पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय है। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। इस बरामदगी से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। उनके हथियारों और संचार साधनों की आपूर्ति बाधित हुई है। सुरक्षा बल लगातार नक्सल विरोधी अभियानों को तेज कर रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां समन्वय से काम कर रही हैं।

पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचा पति, लौटने से इनकार पर फांसी लगाकर दी जान

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के मेघा गांव में पारिवारिक विवाद ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। पत्नी को मनाकर घर ले जाने की उम्मीद लेकर ससुराल पहुंचे 35 वर्षीय युवक ने पत्नी के साथ लौटने से इनकार के बाद कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में शोक और सनसनी का माहौल है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान दीपेश कुमार पटेल (35 वर्ष) निवासी मुरकी, जिला महासमुंद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। इसी कारण 14 जून को

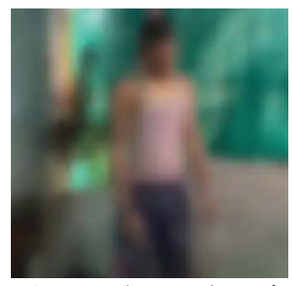

पत्नी नाराज होकर अपने मायके मेघा गांव आ गई थी। जानकारी के मुताबिक, 20 जून को दीपेश अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा। दोनों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन पत्नी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ समय बाद ससुराल के पास एक पान ठेले के बाहर दीपेश का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मगरलोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और परिजनों सहित ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई है कि मृतक नशे का आदी था और पत्नी पर चरित्र को लेकर संदेह करता था, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। यदि जांच में कोई अन्य तथ्य सामने आता है तो उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर में तालाब किनारे मिला विकसित भ्रूणः सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर के रावाभाठा के हृदयलाल चौक पर स्थित ईएसआईसी अस्पताल के पास तालाब किनारे एक विकसित भ्रूण मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि, इसी स्थान पर भ्रूण मिलने की यह दूसरी घटना है। लोगों ने आशंका जताई कि कोई अज्ञात व्यक्ति भ्रूण को यहां फेंककर फरार हो गया। घटना को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलने के बाद खमतराई पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ यह पता लगाने की कोशिश

कर रही है कि भ्रूण यहां कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं।

स्थानीय नागरिकों ने मामले की गंभीर जांच की मांग करते हुए कहा कि बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आना चिंताजनक है। लोगों का कहना है कि यदि यह दूसरी घटना है तो प्रशासन को इस मामले में विशेष निगरानी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रेप के आरोपी को 20 साल की सजाः नाबालिग से किया था दुष्कर्म

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2025 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। मामले की जांच पुलिस ने तेजी से पूरी कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर न्यायालय में चालान पेश किया था।

पुलिस के अनुसार, अपराध क्रमांक 264/2025 में आरोपी मनोज महिलांग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप साबित

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस की ओर से पेश किए सबूतों और गवाहों के बयानों के

आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने आरोपी मनोज महिलांग को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले में पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत निर्धारित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर जांच पूरी की।

बाल अपराधों पर सख्त संदेश

पुलिस का कहना है कि अदालत का यह फैसला बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों पर सख्त संदेश देता है। नाबालिगों से जुड़े मामलों में पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध, शोषण या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। समय पर दी गई सूचना किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1 पोकलेन और 6 हाईवा जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ मुख्यमंत्री के सख्त और 'जीरो टॉलरेंस' के निर्देशों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। सीएम साय के कड़े रुख के बाद प्रदेश भर में खनिज माफियाओं के हौसले पस्त हैं।

इसी कड़ी में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने बीते दो दिनों में एक बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस विशेष अभियान के तहत अवैध गतिविधियों में संलिप्त 1 पोकलेन मशीन और 6 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया है।

खनिज अमले द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को सारंगढ़ तहसील क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान गौण खनिज साधारण रेत का अवैध परिवहन करते हुए 02 हाईवा (वाहन क्रमांक सीजी-07-सीआर-7715 एवं सीजी-13-एक्यू-

0321) को रंगे हाथों पकड़ा गया। इन दोनों वाहनों को जब्त कर सारंगढ़ थाने की सुरक्षा में सौंप दिया गया है। इसी तरह मंगलवार की कार्रवाई के तहत तहसील सारंगढ़ के ही अंतर्गत दोबारा किए गए निरीक्षण में गौण खनिज चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 02 और हाईवा (वाहन क्रमांक सीजी-13-बीबी-2721 एवं सीजी-13-बीबी-2321) पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें भी सारंगढ़ थाने की सुपुर्दगी में रखा गया।

खनिज विभाग की टीम ने उप तहसील कोसीर क्षेत्र के ग्राम पंचायत पासीद में औचक निरीक्षण (सरप्राइज रेड) किया। इस कार्रवाई ने रेत माफियाओं में हड़कंप मचा दिया। मौके पर साधारण रेत के अवैध उत्खनन में सीधे तौर पर संलिप्त 01 पोकलेन मशीन को जब्त कर स्थानीय ग्राम सरपंच की सुपुर्दगी में दिया गया। इसके साथ ही रेत के अवैध परिवहन में लगे 02 अन्य हाईवा (वाहन क्रमांक सीजी-06-एचडी-6457 एवं सीजी-11-बीके-6697) को जब्त कर कोसीर थाने की सुरक्षा में खड़ा कराया गया है।

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के कड़े प्रावधानों के तहत की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि राज्य की संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी रसूखदार या माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। खनिज विभाग ने साफ कर दिया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

रायपुर में हत्या के 2 मामलों में उम्रकैद, पत्नी की कैंची से हत्या, दादी को टंगिया से काटा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में हत्या और हत्या की कोशिश के 3 अलग-अलग मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दो मामलों में आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है, जबकि जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

पहला मामला खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम केशला का है। यहां 44 वर्षीय याज्ञवल्क देवांगन ने अपनी पत्नी तीजन बाई की कैंची मारकर हत्या कर दी थी। घटना 6 मार्च 2024 की है। बताया गया कि पत्नी ने खाना बनाने और कपड़े धोने से मना किया था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने मार डाला। कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

दूसरा मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। गोपाल नगर निवासी 21 वर्षीय दिनेश साहू उर्फदीनू ने अपनी बुजुर्ग दादी की टंगिया (कुल्हाड़ी) से हमला कर हत्या कर दी थी। यह घटना 19-20 अप्रैल 2024 की रात की है। आरोपी ने झोपड़ी में सो रही दादी की गर्दन पर हमला किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से दादी की थैली से लूटे गए 540 रुपए भी बरामद किए थे। कोर्ट में आरोपी इस रकम को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। कोर्ट ने आरोपी दिनेश साहू को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

युवक पर लोहे के पट्टे से हमला, तीन को 7 साल की सजा

तीसरा मामला जानलेवा हमले का है। 24 दिसंबर 2023 को तेली तालाब के पास जितेंद्र पटेल नाम के युवक पर लोहे के पट्टे, डंडे और मुक्कों से हमला किया गया था। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इस मामले में पुलिस ने अभनपुर क्षेत्र के राजेश मारकंडे, तुलाराम उर्फ विक्की मारकंडे और सुनील मारकंडे को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने माना कि हमला जान लेने की नीयत से किया गया था। तीनों आरोपियों को 7-7 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

वाहन चोरी का खुलासा, 3 शातिर चोर गिरफ्तार

महासमुंद। जिले की बसना पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई कुल 6 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 3 लाख 20 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने न केवल उक्त बाइक चोरी की वारदात को स्वीकार किया, बल्कि अन्य पांच मोटरसाइकिलें चोरी करना भी कबूल किया। गिरफ्तार आरोपियों में अशोक कुमार साहू (25 वर्ष), डिजेश्वर यादव (23 वर्ष) और अनुराग दास (19 वर्ष) शामिल हैं। तीनों आरोपी बसना क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कुल 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें बजाज प्लेटिना, एचएफ डीलक्स, हीरो सुपर स्प्लेंडर सहित अन्य वाहन शामिल हैं।

खास खबर

सुघ्घर छत्तीसगढ़ की तैयारियों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शीघ्र ही प्रारंभ होगा। अभियान के तहत शासन की 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा प्रत्येक पात्र परिवारों को पहुंचाया जाएगा। यह अभियान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने महानदी भवन में इस संबंध में अधिकारियों से तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। योजना के फायदे से कोई वंचित न रहे इसके लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रक्रिया शुरू, जनवरी तक मिलेगा पैसा

रायपुर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। योजना का लाभ राज्य के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा। शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया 20 जून 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जबकि नवीन आवेदन 1 अगस्त 2026 से स्वीकार किए जाएंगे। जनवरी 2027 तक छात्रवृत्ति राशि के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालकों की वार्षिक आय सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पूर्व वर्ष की अंकसूची एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

वीबी-जी राम जी का मंत्रिपरिषद ने किया अनुमोदन, राज्य शासन ने 4000 करोड़ का किया प्रावधान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। योजना के तहत ठोस और स्थायी प्रकृति के कार्य किए जाने हैं। इसमें केन्द्र और राज्य शासन का अंशदान 60:40 रहेगा। राज्य शासन ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर दिया है।

भारत सरकार के अधिनियम, 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविकामूलक परिसंपत्तियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्राम

पंचायत आधारित समेकित विकास, विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा पीएम गति शक्ति से समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विकास कार्यों की बेहतर कार्ययोजना एवं निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए पारदर्शिता, सुशासन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से 'अटल आजीविका निर्णय लिया। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

2036 ओलंपिक की मेजबानी पर भारत का दावा

ओलंपिक मेजबानी के पक्ष में रोपे 2036 पौधे मुख्यमंत्री साय ने किया रुद्राक्ष का पौधरोपण

- छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर वातावरण और आधुनिक अधोसंरचना का हो रहा विकास

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित वृक्षारोपण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह में शामिल होकर रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए खेल और पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्र निर्माण के दो महत्वपूर्ण आधार बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का दावा प्रस्तुत किया है। इसी राष्ट्रीय संकल्प और आकांक्षा को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए कार्यक्रम में 2036 पौधों का रोपण किया जा रहा है। यह केवल वृक्षारोपण अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ, हरित और सशक्त भारत का संकल्प भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बेहतर वातावरण और आधुनिक अधोसंरचना विकसित की जा रही है ताकि युवा अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की सफल मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ। वहीं बस्तर ओलंपिक जैसे अभिनव आयोजन ने दूरस्थ अंचलों की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बजट प्रावधान कर रही है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा वन विभाग के खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री श्री साय एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने देश में खेल संस्कृति को नई पहचान दी है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार युवा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हर संभव अवसर उपलब्ध करा रही है। बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन भी युवाओं को नई दिशा प्रदान कर रहा है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. विक्रम सिंह सिसोदिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पाण्डेय, बीएसएफ के आईजी संजय पंत सहित अनेक जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रख्यात शिक्षाविद्,भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सशक्त प्रहरी थे। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। उनके विचार, संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र एवं राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश की राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान किया तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र की अखंडता और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर ही हम राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, श्री राम गर्ग सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

शेडनेट में करेला-खीरा-तोरई-बरबट्टी खुले में लगाई मिर्ची और हुए मालामाल

- आधुनिक खेती से सालभर में 7 लाख रुपये की आय

श्रीकंचनपथ समाचार

बीजापुर। कभी परंपरागत खेती तक सीमित रहे बीजापुर जिले के ग्राम पोलेम के किसान कन्हैया आत्रम आज आधुनिक बागवानी तकनीक अपनाकर आर्थिक समृद्धि की नई मिसाल बन गए हैं। सब्जियों को जरूरत के हिसाब से शेडनेट और खुले में लगाकर न केवल उन्होंने पैदावार बढ़ाई बल्कि बाजार तक बेहतर पहुंच ने उन्हें मालामाल भी कर दिया।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यानिकी विभाग के सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से कन्हैया आत्रम ने 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित किया, जिससे उनकी खेती की तस्वीर ही बदल गई।

शेडनेट हाउस में कन्हैया आत्रम करेला, खीरा, तरोई और बरबटी

जैसी सब्जियों की उन्नत खेती कर रहे हैं। इस खेती से उन्हें अब तक लगभग 2 लाख रुपये का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसमें सभी खर्च निकालने के बाद 1.80 लाख रुपये की शुद्ध आय हुई। वहीं खुले खेत में लाल मिर्च की खेती से उन्होंने करीब 7 लाख रुपये का उत्पादन हासिल किया। लगभग 2 लाख रुपये की लागत के बाद उन्हें 5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

कन्हैया आत्रम का कहना है कि उद्यानिकी विभाग की योजनाओं, अनुदान और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन ने उन्हें आधुनिक खेती अपनाने का आत्मविश्वास दिया।

आधुनिक कृषि में उनकी सफलता अब क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है और यह साबित कर रही है कि वैज्ञानिक खेती अपनाकर कम क्षेत्र में भी बेहतर उत्पादन और अधिक आय अर्जित की जा सकती है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक करें नामांकन

रायपुर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सर्वोच्च बाल सम्मान माना जाता है, जो उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अभिभावक, स्कूल के शिक्षक/प्राचार्य, सामाजिक संस्थाएं और अन्य व्यक्ति भी योग्य बच्चों का नामांकन कर सकते हैं। सभी आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी के लिए awards.gov.in पर विजिट किया जा सकता है।

मिडिल पास करने तक 25 तक पहाड़ा और धाराप्रवाह अंग्रेजी-हिन्दी पढ़ने में दक्ष हो जाने चाहिए बच्चे : यादव

- अगले साल एक अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र
- समय पर मिलेगी पाठ्य पुस्तक, गणवेश और सायकल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा हेतु आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

श्री यादव ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में साफ-सफाई, आवश्यक मरम्मत कार्य, पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश

वितरण, साइकिल वितरण तथा अति आवश्यक कार्यों के लिए जारी राशि के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्यालय छोड़ चुके (ड्रॉपआउट) बच्चों को विशेष अभियान चलाकर 31 जुलाई तक पुन: विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिक्षकों की VSK App के माध्यम से शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को बारहखड़ी एवं 20 तक के पहाड़े तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को 25 तक के पहाड़े, हिंदी एवं अंग्रेजी की धाराप्रवाह रीडिंग अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करने तथा सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में जर्जर विद्यालय भवनों की सूची तैयार कर ऐसे भवनों को चरणबद्ध रूप से डिस्मेंटल करने के निर्देश दिए गए। भवनविहीन विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) द्वारा किए जाने के निर्देश भी दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में संलग्न शिक्षकों की मूल पदस्थापना स्थल पर तत्काल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

इसके अलावा रमसा प्राप्त विद्यालयों का नियमित निरीक्षण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत केंद्रीकृत किचन व्यवस्था, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना आदि की प्रगति की समीक्षा की गई।

29-30 जून को आयोजित होगा रामगढ़ महोत्सव

रायपुर। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत के प्रतीक रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन आगामी 29 एवं 30 जून को दो दिवसीय रूप में किया जाएगा। आषाढ़ प्रथम दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने सरगुजा कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने विकासखंड उदयपुर स्थित रामवनगमन पर्यटन परिपथ स्थल एवं विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री वसंत ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर हेलीपैड, मुख्य मंच, पार्किंग, पंडाल, बैठक व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए जाने वाले प्रदर्शनी एवं विभागीय स्टॉलों की तैयारियों का अवलोकन किया। इसके उपरांत उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां को पूरा करने पर जोर दिया।

पर्यावरण संरक्षण मंडल का रायगढ़ में लगाई कार्यशाला

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : 82 पंचायतों ने लिया प्रशिक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर निगम ऑडिटोरियम, रायगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य हितधारकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह एवं श्री पुरुषोत्तम पंडा ने मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रतिभागियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को नियमों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण सत्र में घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कचरे के

वैज्ञानिक प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को 4-वे कचरा पृथक्करण प्रणाली की जानकारी दी गई, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी अपशिष्ट तथा घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को अलग-अलग संग्रहित करने एवं उनके सुरक्षित निस्तारण की प्रक्रिया समझाई गई।

विशेषज्ञों ने बताया कि स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण करने से अपशिष्ट प्रबंधन अधिक प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल बनता है। ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण, परिवहन एवं अंतिम निस्तारण की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित करने पर भी बल दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि कचरे को खुले में फेंकना, जलाना अथवा भूमि में दबाना नियमों के विरुद्ध है जिसमें वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम में मुख्य रसायनज्ञ नवीन चंद्र मालवीय, वैज्ञानिक श्वेता खाखा, वैज्ञानिक सतीश पटेल, पर्यावरण विभाग के अधिकारीगण, जिला पंचायत से एपीओ वीरेंद्र सिंह राय, जिला सलाहकार (एसबीएम-जी) अर्जुन मेहेर, विभिन्न जनपद पंचायतों की एसबीएम-जी टीम, सरपंच, सचिव उपस्थित रहे।

चावल पापड़ उद्योग से आत्मनिर्भर बन रही हैं दुर्ग जिले की ग्रामीण महिलाएं

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिले के ग्राम पंचायत ननकट्टी की विद्यावती चौधरी आज ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर उन्होंने न केवल अपने जीवन को नई दिशा दी, बल्कि गांव की अनेक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया।

आराध्या स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष एवं एफएलसीआरपी के रूप में कार्यरत विद्यावती चौधरी ने समूह की बचत एवं ऋण राशि का उपयोग करते हुए चावल पापड़ निर्माण और सिलाई केंद्र की शुरुआत की। यह कार्य छोटे स्तर पर शुरू हुआ, जहां समूह की महिलाएं घर-आंगन में मिलकर पापड़ तैयार करती थीं। सीमित संसाधनों के बीच

महिलाओं ने मेहनत, लगन और गुणवत्ता को अपनी ताकत बनाया।

बेहतर गुणवत्ता के कारण उनके उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती गई। आज समूह द्वारा तैयार किए गए पापड़ स्थानीय बाजारों में अपनी पहचान बना चुके हैं और प्रतिमाह हजारों रुपये का कारोबार हो रहा है। इस उद्यम ने समूह की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। नियमित आय मिलने से परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों की पूर्ति अब अधिक आसानी से हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हुई हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950